

निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर दिल्ली जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई

कर चोरी और राजस्व के नुकसान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी दिल्ली सरकार: रेखा गुप्ता



हरिभूमि न्यूज़ ►► नई दिल्ली

दिल्ली सरकार कर चोरी और राजस्व के नुकसान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर दिल्ली जीएसटी विभाग की

बड़ी कार्रवाई के दौरान करीब 5 करोड़ रुपये का माल पकड़ने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग ने रेलवे अधिकारियों के समन्वय से

बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर करीब 5 करोड़ रुपये मूल्य के कॉपर स्क्रेप समेत लगभग 50 टन माल की खेप जब्त की है। विभाग को खुफिया जानकारी मिली थी कि रेलवे नेटवर्क के जरिए अनिवार्य

दस्तावेजों, जैसे इनवॉइस और ई-वे बिल के बिना माल का परिवहन किया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर विभाग ने रेलवे अधिकारियों के साथ मिलकर यह कार्रवाई की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, सरकार का लक्ष्य

बिना जरूरी दस्तावेजों के हो रहा था माल का परिवहन

पकड़े गए माल के साथ आवश्यक इनवॉइस और ई-वे बिल उपलब्ध नहीं थे। विभाग द्वारा अब माल और उससे संबंधित दस्तावेजों का विस्तृत सत्यापन किया जा रहा है। साथ ही, जीएसटी कानून के तहत माल के परिवहन से संबंधित वैधानिक अनुपालन की भी जांच की जा रही है। विभाग के अनुसार, यह कार्रवाई सड़क मार्ग के अलावा रेलवे नेटवर्क के जरिए होने वाले माल के परिवहन पर निगरानी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय और रेलवे मार्गों की निगरानी बढ़ाकर बिना हिस्सा-किताब के माल, अनियमित दस्तावेजों और संभावित कर चोरी के मामलों का पता लगाने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार कर चोरी और राजस्व के नुकसान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार का लक्ष्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि ऐसी प्रभावी व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें कारोबार पारदर्शी तरीके से हो और प्रत्येक देय कर की वसूली सुनिश्चित हो। रेलवे सहित माल परिवहन के सभी माध्यमों पर निगरानी बढ़ाकर जीएसटी अनुपालन को मजबूत किया जाएगा। सुशासन, पारदर्शिता और सरकारी राजस्व की सुरक्षा दिल्ली सरकार की प्राथमिकताओं में है और कर चोरी में शामिल तत्वों के खिलाफ कानून के अनुरूप सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि ऐसी प्रभावी व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें कारोबार पारदर्शी तरीके से हो और प्रत्येक देय कर की वसूली सुनिश्चित हो। यह खेप आंध्र प्रदेश के रंगिगुंटा से रवाना हुई ट्रेन

के जरिए लाई गई थी और हजारत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंची थी। जांच के दौरान अधिकारियों ने करीब 25 टन कॉपर स्क्रेप जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये है। इसके

अलावा करीब 25 टन मिश्रित स्क्रेप, कपड़े और अन्य सामान भी मिला, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपये है। इस प्रकार पकड़े गए माल का कुल अनुमानित मूल्य करीब 5 करोड़ रुपये है।

सिंधु बॉर्डर पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखने के आरोप में तीन लोग गिरफ्तार

एजेंसी ►► नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने घोषित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नु के निर्देश पर यहां सिंधु बॉर्डर पर कथित तौर पर आपत्तिजनक नारे लिखने और खालिस्तान समर्थक भित्तिचित्र बनाने के मामले में पंजाब से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। सिंधु बॉर्डर पर दीवारों पर ये नारे और भित्तिचित्र छह सितंबर को मिले थे जिसके बाद दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' (एसएफजे) के प्रमुख पन्नु ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा कर घटना की जिम्मेदारी ली थी। सूत्रों ने बताया कि आरोपियों की पहचान प्रीतपाल, हरमिंदर सिंह और शीशपाल के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि जांचकर्ताओं ने सिंधु बॉर्डर की सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर उनकी गतिविधियों का पता लगाया जिसके बाद उन्हें पंजाब के फरीदकोट से गिरफ्तार किया गया। सूत्रों ने कहा कि आरोपियों ने जिस कार का कथित तौर पर इस्तेमाल किया था, उसे भी



बरांमद कर लिया गया है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रीतपाल कथित तौर पर पन्नु के सीधे संपर्क में था और पन्नु ने ही उसे सिंधु बॉर्डर के पास दीवारों पर आपत्तिजनक नारे लिखने का निर्देश दिया था। सूत्रों ने कहा कि जांचकर्ता इस बात की भी पड़ताल कर रहे हैं कि प्रीतपाल कहीं पाकिस्तान में मौजूद आतंकी तत्वों के भी संपर्क में तो नहीं था। उन्होंने बताया कि प्रीतपाल के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूपीए) के तहत पहले से एक मामला दर्ज है। जांच के सिलसिले में विशेष प्रकोष्ठ और खुफिया ब्यूरो (आईबी) की टीम अलीपुर थाने में तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

डेढ़ लाख रुपये की टगी मामले में तीन लोग किए अरेस्ट

एजेंसी ►► नई दिल्ली

गुजरात के एक व्यक्ति से कम कीमत पर वॉशिंग मशीन के पुर्जों बेचने के नाम पर की गई ठगी की राशि वसूलने और ठिकाने लगाने में इस्तेमाल तीन खातों के धारकों को पकड़ा गया है, जिनमें दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र और एक बाइक टेक्सि चालक शामिल हैं। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि गुजरात के पाटन निवासी एक व्यक्ति से कथित तौर पर 1.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। पॉइंट ने वॉशिंग मशीन के पुर्जों के लिए ऑनलाइन भुगतान किया था, लेकिन उसे वादे के मुताबिक सामान नहीं मिला। अधिकारियों ने बताया कि धोखाधड़ी से प्राप्त राशि कई खातों के जरिये प्राप्त की गई और एस राशि का कुछ हिस्सा पूर्वी दिल्ली के एक एटीएम से निकाला गया। पुलिस ने आरोपियों की पहचान दिल्ली के शकरपुर निवासी विकास सोनी (22), नैतिक (21) और त्रिलोकपुरी निवासी सागर (31) के तौर पर की। पॉइंट से ऑनलाइन शिकायत मिलने के बाद, पुलिस ने सात सितंबर को औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज की।

पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया कि धोखाधड़ी से हासिल की गई रकम का एक हिस्सा नैतिक के एक बैंक खाते में जमा किया गया था। उसने बताया कि जांच में पैसे के अंतरण में विकास की कथित भूमिका की जानकारी मिली और दोनों को पकड़ लिया गया। बाद में, पुलिस ने सागर को भी पकड़ लिया। अधिकारियों ने बताया कि विकास बीए तृतीय वर्ष का छात्र है और कथित तौर पर उसने ठगी से प्राप्त राशि लेने के लिए अपने खाते के इस्तेमाल की अनुमति दी। उन्होंने बताया कि नैतिक दिल्ली विश्वविद्यालय के मुक्त शिक्षा विद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र है और उसने ठगी के पैसे प्राप्त किए व निकाले। पुलिस के मुताबिक, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और बाइक टेक्सि चालक सागर ने कथित तौर पर कमीशन पर अपने खाते का इस्तेमाल करने की अनुमति ठगों को दी और नकदी निकाली। पुलिस ने विकास के पास से एक आईफोन 13 बरामद किया।

उन्होंने कहा कि इस उपकरण में कथित तौर पर लेन-देन से जुड़ी चैट और अन्य वाटरचैट मौजूद है तथा डिजिटल सबूत के लिए इसकी जांच की जा रही है।

भारतीय मजदूर संघ ने सरकार को चेताया, मांगे नहीं मानी तो 21 को दिल्ली सहित देशभर में करेंगे प्रदर्शन

नई दिल्ली। भारतीय मजदूर संघ ने सरकार को चेताया है कि अगर संगठन द्वारा लंबे समय से की जा रही मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी 21 सितंबर को दिल्ली सहित देशभर में राज्य परिवहन कर्मचारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। इस बारे में महासंघ के संगठन मंत्री कैलाश मलिक ने बताया कि परिवहन संबंधित मामलों को लेकर हमने लंबे समय से इंतजार किया लेकिन किसी ने सुना नहीं। अब फैसला लिया गया है कि अगर सरकार नहीं चेती तो 21 सितंबर 2026 को एक साथ देश के सभी प्रदेशों में राज्य परिवहन कर्मचारी सड़कों पर आकर प्रदर्शन करेंगे। मलिक ने बताया कि मजदूर संघ मिल-बैठकर समझौते के पक्ष में है, लेकिन सरकार को लग रहा है कि मजदूर संघ सो रहा है। अब आन्दोलन का बिगुल बज गया है, यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। मलिक ने बताया कि हमारी प्रमुख मांग है कि सभी राज्य परिवहन निगमों में अनुबंध प्रथा समाप्त की जाए। जो अनुबंध पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें स्थान दिया जाए और आगे अनुबंध प्रथा बंद हो। जब तक स्थान नहीं दिया जाता तब तक अनुबंध कर्मचारियों को स्थान कर्मचारियों के समान वेतन व अन्य लाभ दिए जाए।

महिला की हत्या के मामले में पति और उसकी प्रेमिका गिरफ्तार

एजेंसी ►► नई दिल्ली

दिल्ली के प्रहलादपुर में पिछले महीने हुई एक महिला की हत्या के मामले में उसके 22 वर्षीय पति और कथित प्रेमिका को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि जांच के दौरान पता चला कि महिला की हत्या पति और प्रेमिका के बीच संबंधों के कारण की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी मोहम्मद लाल बाबू उर्फ जाहिद अली और रुखसार खातून को दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, पटना, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और मुंबई में 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल समेत व्यापक जांच के बाद गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों के अनुसार, लाल बाबू ने कथित रूप से रुखसार के साथ मिलकर साजिश रची और प्रहलादपुर स्थित

एक घर के बाथरूम में पत्नी सबीला खातून की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद 29 अगस्त को शाहबाद डेयरी थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसने कहा कि लाल बाबू और सबीला प्रहलादपुर में रह रहे थे। आरोप है कि लाल बाबू का रुखसार के साथ संबंध था और वह उससे शादी करना चाहता था। पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद लाल बाबू अपने नाबालिग बेटे के साथ दिल्ली से मोनडा की ओर भाग गया, जहां उसने अपने मेमेरे भाई मोहम्मद ओसामा से संपर्क किया। पुलिस ने बताया कि ओसामा ने कथित रूप से लाल बाबू के ठहरने की व्यवस्था की और अन्य मदद दी तथा गिरफ्तारी से बचने के लिए बिहार जाने में उसकी सहायता की। जांच

के दौरान उसे पहले ही गिरफ्तार कर व्याधिक हिरासत में भेज दिया गया था। हत्या के बाद पुलिस ने कई जगहों पर तलाशी ली और आरोपियों का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच तथा मौके पर जाकर सत्यापन किया। पुलिस ने बताया कि जांचकर्ताओं ने अपराध के बाद लाल बाबू द्वारा कथित रूप से इस्तेमाल किए गए रास्ते और स्थानों का पता लगाया और आखिरकार उसे तथा रुखसार को खोज निकाला। अधिकारियों के अनुसार, जांच में सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल, तकनीकी जानकारी और कई राज्यों में जुटाई गई स्थानीय सूचनाओं का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने बताया कि बिहार के सीतामढ़ी का निवासी लाल बाबू मुख्य आरोपी है और वह मृतका का पति है।

एमएलए झा ने लगाए पांचवीं मंजिल को सील करने में भेदभाव के आरोप

नई दिल्ली। बुराड़ी से आप पार्टी के विधायक संजीव झा ने आरोप लगाया कि मेरे क्षेत्र में खतरनाक बिल्डिंग गिराने और पांचवीं मंजिल को सील करने के मामले में भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ भाजपा सरकार आम लोगों के छोटे छोटे मकानों पर कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बिल्डरों द्वारा बनाए 5-6 मंजिला इमारतों पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। दिल्ली सरकार ने जब कोई नियम बनाया है तो कार्रवाई सब पर एक समान होनी चाहिए। बड़ी उमसीढ़ी के साथ भाजपा को लाने वाली दिल्ली की जनता आज उसी के आतंक से त्रहिए कर रही। उन्होंने कहा कि पांचवीं मंजिल की सीलिंग और डैमेज बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर जिस तरह अभियान चल रहा है, उसे लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। संजीव झा ने कहा कि पूरी दिल्ली में जब से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी सरकार ने पांचवीं मंजिल को सील करने और डैमेज बिल्डिंग को डेमोलिश करने का निर्णय लिया है, तब से किसी भी बड़े बिल्डर का मकान डेमोलिश नहीं हो रहा है। कोई आम आदमी अगर मकान बना रहा है तो उसको डेमोलिश कर दे रहे हैं, लेकिन जो बड़े बिल्डर 50 से 100 कमरे और पांच-छह फ्लोर बना रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह आदेश इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं कि इस तरह की गतिविधियां रुके, बल्कि इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि वसूली में इनका हिस्सा और जनता का एक्सटॉर्शन बढ़ जाए।

भाजपा नेताओं के चल रहे है पीजी हाउस, एमएलए ने सत्य निकेतन में किया अवैध कब्जा: सौरभ

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा विधायक अनिल शर्मा सहित अन्य भाजपा नेता पर कहा कि अवैध तरीके से भारी संख्या में पीजी हाउस बनाए जा रहे हैं। भारद्वाज ने कहा कि भाजपा विधायक अनिल शर्मा के पिता के नाम पर है पीजी की जमीन, जबकि उनका बेटा व उनके परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इतना ही नहीं भाजपा के दूसरे नेता भी हैं जिनका बेटा भी इसमें बराबर का हिस्सेदार है। अनिल शर्मा के पिता ने 600 वर्ग गज में बनी पीजी को चलाने के लिए अपने पोते की कंपनी को लीज पर दी है। भारद्वाज ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफैयर्स की वेबसाइट से दस्तावेज निकाल कर अनिल शर्मा के झूठ को बेनकाब कर दिया है। अनिल शर्मा के पिता ने 600 वर्ग गज में बनी पीजी को चलाने के लिए अपने पोते की कंपनी नेदर होल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लीज पर दी है। भाजपा विधायक की पोले पूरी तरह खुल गई है। क्या सांसद बाबुरी स्वरज इस पर कोई टिप्पणी करेगी। भारद्वाज ने कहा कि सत्य निकेतन में जो पीजी चल रहे हैं, उन्हें भाजपा के बड़े-बड़े नेता चला रहे हैं।

भाजपा में दलित मंडल अध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं तो आम दलित कितना सुरक्षित: आप

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने कहा है कि जब भाजपा में उनका अपना दलित मंडल अध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं तो आम दलित लोग कितना सुरक्षित होंगे इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। आप एमएलए का कहा है कि भाजपा के एक विधायक ने अपने ही मंडल के दलित अध्यक्ष को घर पर बंधक बनाकर पीटा और जाति सूचक गातियां दीं। लेकिन इस गंभीर मसले पर भाजपा की चुप्पी से साफ हो गया कि दिल्ली में दलित होना ही सबसे बड़ा अपराध बन गया है। कुलदीप ने कहा कि दिल्ली पुलिस को चाहिए कि इस मामले में एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करे और भाजपा अपने विधायक को तुरंत निर्लंबित करे। उन्होंने दलित समाज से भी आह्वान किया कि अगर अब भी आप इस घटना के खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो कल किसी और दलित का नंबर आना तय है।

फसलों में किसी प्रकार का छिड़काव ना करें किसान: पूसा

नई दिल्ली। वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों को सलाह है कि किसी प्रकार का छिड़काव ना करें तथा खड़ी फसलों (दलहन की फसलों, मक्का आदि) व सब्जी नर्सियों में जल निकास का उचित प्रबंधन रखे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पूसा) के कृषि परामर्श सेवाओं, कृषि मीतिक संभाग की नोडल अधिकारी डॉ. अनन्ता वशिष्ठ ने किसानों को यह सलाह जारी की है। वहीं, कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह देते हुए कहा है कि धान की फसल इस समय मुख्यतः बाली बनने वाली स्थिति में है अतः फसल में कीटों की निगरानी करें। तना छेदक कीट की निगरानी हेतु फिरोजगंज प्रखं प्रति 3-4 प्रति एकड़ लगाए। यदि तना छेदक कीट का प्रकोप अधिक हो तो करटपदवाई 4 प्रतिशत दाने 10 किलोग्राम प्रति एकड़ का बुरकाव करें। सलाहकार समिति के कृषि वैज्ञानिक डॉ. सुभाष नटराजा पिल्ले (अध्यक्ष, कृषि मीतिक संभाग), डॉ. सचिन सुरेश श्रेणी (परियोजना समन्वयक, मधुमत्स्यी पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना) डॉ. दिनेश कुमार (प्रधान वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग), डॉ. ए. के. सिंह (प्रधान वैज्ञानिक व इक्वाज, केंटेट) डॉ. गौगराज सिंह जाट (वरिष्ठ वैज्ञानिक, सब्जी विज्ञान संभाग), डॉ. हिरणू मार्या (वरिष्ठ वैज्ञानिक, पादप रोग संभाग) ने कहा कि इस समय धान की फसल को नष्ट करने वाली बाउज प्लांट होएकरा आक्रमण आरंभ हो सकता है अतः किसान भाई खेत के अंदर जाकर पौध के निचली भाग के स्थान पर मक्खनजुमा कीट का निरीक्षण करें। यदि प्रकोप अधिक दिखाने दें तो इमिडाक्लोप्रिड दवाई 1.0 मि. ली. प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा
(धारा 82 सीआरपीसी / 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 देखिए) मेरे समक्ष परिवार किया गया है कि अभियुक्त श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री कंपनी शाह (सीटी / जीडी नंबर 107333102), निवासी पीओ परबत्ता, पीएस परबत्ता, जिला खगड़िया, बिहार-851216 (फोन नंबर 6204762380) कार्यालय: बाराचक 5, सीआईएसएफ बैरिक, सेक्टर-5, रोहिणी रिहावा, दिल्ली-110085) के कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या एम / 37 / 2024, धारा 138 एनआई एक्ट के तहत थाना: आईजीआई हवाई अड्डा, नई दिल्ली के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त श्री अश्वनी कुमार नहीं मिल रहा है और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि श्री अश्वनी कुमार फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। अतः इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या एम / 37 / 2024, धारा 138 एनआई एक्ट के तहत थाना: आईजीआई हवाई अड्डा, नई दिल्ली के उक्त अश्वनी कुमार , से अपेक्षा किया जाता है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवार का उत्तर देने के लिए दिनांक 29.10.2026 को या इससे पहले हाजिर हो। आदेशानुसार स्नेहिल शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (ननआई एक्ट)-01, कमरा नं.43 पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली
DP/12959/GIA/2026

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा
धारा 82 सीआरपीसी / 84 बीएनएसएस देखिए मेरे समक्ष परिवार किया गया है कि अभियुक्त शाहिद पुत्र: फरीद अहमद पता: मकान नं.-सुणी नं. 59, घरम कांटा के पास, 18 वलार्ड विस्वास नगर, शाहदरा, -110032 दिल्ली ने case FIR No. 95/2018 U/s 324/326 IPC, थाना: विवेक विहार, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त शाहिद मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानमद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त शाहिद फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है है) इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि case FIR No. 95/2018 U/s 324/326 IPC, थाना: विवेक विहार, दिल्ली के उक्त अभियुक्त शाहिद से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवार / मुकदमा का उत्तर देने के लिए दिनांक 16.10.2026 को या उससे पूर्व हाजिर हो। आदेशानुसार श्री मोहित शर्मा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रूम नं. 59, तीसरी मंजिल, शाहदरा जिला कड़कड़झा कोर्ट, दिल्ली
DP/12805/SHD/2026 (Court Matter)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा
धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देखिए मेरे समक्ष परिवार किया गया है कि अभियुक्त लोकेश यादव , पुत्र स्वर्गीय अल्बेल सिंह निवासी F-237, गली नंबर 11, मोलरबंद एक्सटेंशन, बदरपुर, नई दिल्ली ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 148/2026 धारा 20/61/85 NDPS अधिनियम थाना बदरपुर, नई दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त लोकेश यादव मिल नहीं रहा है, और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त लोकेश यादव फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको को छिपा रहा है)। इसके खिलाफ मामनीय अदालत द्वारा धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कार्यवाही जारी हो चुकी है। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 148/2026 धारा 20/61/85 NDPS अधिनियम थाना बदरपुर, नई दिल्ली के उक्त अभियुक्त लोकेश यादव से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष उक्त परिवार का उत्तर देने के लिए 04.11.2026 को या उससे पहले हाजिर हो। आदेशानुसार: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-04/विशेष न्यायाधीश (NDPS), कोर्ट नंबर 312, दक्षिण-पूर्व ज़िला, साकेत कोर्ट, नई दिल्ली।
DP/12529/SE/2026

लोक निर्माण विभाग दो वर्ष में पूरा करेगा निर्माण कार्य

‘आपराधिक मामलों की वैज्ञानिक जांच होगी तेज, शेख सराय में बनेगी फोरेंसिक लैब’

हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

दिल्ली के शेख सराय में 151.81 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला बनेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में आपराधिक मामलों की वैज्ञानिक जांच के लिए फोरेंसिक सुविधाओं को और मजबूत करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई व्वय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में शेख सराय में अत्याधुनिक क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (आरएफएसएल) के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना के लिए 151.81 करोड़ रुपये के



बजट को भी स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को

‘कानूनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी’

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से गृह विभाग और दिल्ली पुलिस को नए आपराधिक कानूनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कारण आपराधिक मामलों में फोरेंसिक जांच की मांग में काफी वृद्धि हुई है। नई आरएफएसएल इस बड़ी हुई मांग को पूरा करने में सहायता करेगी। इससे आपराधिक मामलों में वैज्ञानिक जांच के लिए आवश्यक क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

‘न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया के लिए है आवश्यक’

मुख्यमंत्री ने बताया कि नई आरएफएसएल रोहिणी स्थित मौजूदा एफएसएल की वैज्ञानिक सहायता को मजबूत करेगी। फोरेंसिक विज्ञान आपराधिक मामलों में वैज्ञानिक जांच के साथ-साथ आपराधिक मुकदमों और न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। नई प्रयोगशाला से राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक सहायता को भी मजबूती मिलेगी। इसका विशेष लाभ दक्षिण, दक्षिण-पूर्व और मध्य दिल्ली के जिलों को मिलेगा।

परियोजना का निर्माण कार्य दो वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य दिया है। शेख सराय में बनने वाली नई क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला लगभग 6,300 वर्गमीटर के भूखंड पर बनाई जाएगी और

इसका कुल निर्मित क्षेत्र 18,300 वर्गमीटर होगा। पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित यह भवन वैज्ञानिक जांच की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एकिकृत फोरेंसिक सुविधा के रूप में विकसित किया जाएगा।

‘साक्ष्यों की जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट की प्रक्रिया होगी तेज’

दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि नई क्षेत्रीय एफएसएल के शुरू होने के बाद मामलों से जुड़े साक्ष्यों की जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम अधिक तेज और सुगम हो जाएगा। नई सुविधा से साक्ष्य आधारित जांच को मजबूती मिलेगी। साथ ही, इससे आपराधिक मामलों को न्यायालयों में समय पर निपटाने में सहायता मिलेगी। नई क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण से दिल्ली में वैज्ञानिक जांच के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। विशेष रूप से दक्षिण, दक्षिण-पूर्व और मध्य दिल्ली के जिलों को आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ यह सुविधा रोहिणी स्थित एफएसएल को वैज्ञानिक सहायता मजबूत करने में भी सहायक होगी।

सहरावत ने केशोपुर में किया डेंगू दिवस-जागरूकता अभियान का उद्घाटन

नई दिल्ली। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने शनिवार को केशोपुर में डेंगू दिवस-जागरूकता अभियान का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर मच्छर जनित बीमारियों से बचाव एवं रोकथाम के उपायों पर आधारित प्रदर्शनी का भी सांसद ने अवलोकन किया। सांसद ने वार्ड-103 में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 8 नई कुड़ा संग्रहण गाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सांसद सहरावत ने डेंगू मलेरिया एवं चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए नागरिकों से सहयोग की अपील की। कार्यक्रमों में सहरावत के अलावा दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य राजीव बब्बर, वार्ड समिति अध्यक्ष हरीश ओबरॉय, उपाध्यक्ष, पंचायी क्षेत्र कर्नल विनोद अत्री, उप स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजय कुमार आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि व निगम के अधिकारी-कर्मचारी आदि मौजूद थे। अपने संबोधन में सांसद सहरावत ने कहा कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय मच्छरों को पनपने से रोकना है।

‘संवाद की संस्कृति का देश है भारत’

नई दिल्ली। भारत संवाद की समृद्ध परंपरा और उसकी विशिष्ट सांस्कृतिक भावभूमि का देश है। कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलापति प्रो. बलदेव भाई ने शनिवार को मंत्री हाउस स्थित त्रिवेणी कला संगम के सभागार में यह बात कही। सभागार में संस्कृति पर्व के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि भारत संवाद की संस्कृति का देश है और हमारी सांस्कृतिक परंपरा की निर्मिति के मूल में संवाद ही रहा है। बता दें कि साहित्य संस्कृति फाउंडेशन के आठवें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यह आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ. संजय पासवान ने कहा कि संवाद और संधिधान ही सभी तरह की समस्याओं के समाधान का एक मात्र साधन है। उन्होंने कहा कि एक ही समय में विचार की अलग-अलग दिशा और दृष्टि के कारण जिसे कुछ लोग संस्कृति समझते हैं उसी को दूसरे कुछ लोग विकृति मान बैठते हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि ऐसा प्रायः परम्पराओं के ज्ञान के अभाव में ही होता है इसलिए हमें भारत की विशिष्ट परम्पराओं का ज्ञान होना चाहिए तथा सभी सांस्कृतिक परम्पराओं के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। उद्घाटन सत्र का संचालन मिरांडा हाउस कॉलेज की प्रो. संगीता राय ने किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के डॉ. मनीष ने किया। संस्कृति पर्व के अवसर पर साहित्य संस्कृति फाउंडेशन की ओर से चर्चित कथाकार कवयित्री अलका सिन्हा को साहित्य सम्मान, सश्रुता अग्रजान केंद्र के संस्थापक रविशंकर को संस्कृति श्री सम्मान, ध्रुवाद गायक सुमीत आनंद पाण्डेय को कला श्री सम्मान एवं न्यूरो सर्जन डॉ. मनीष कुमार को सेवा श्री सम्मान से सम्मानित किया गया।

आधार और राशन कार्ड में एक ही मोबाइल नंबर होना जरूरी राशन वितरण व्यवस्था को डिजिटल बनाने की तैयारी कर रही सरकार

हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

दिल्ली सरकार उचित दर को दुकानों (एफपीएस) के माध्यम से राशन वितरण व्यवस्था को और अधिक डिजिटल एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसी कड़ी में राशन कार्डधारकों के लिए सीबीडीसी (केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा) व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया चल रही है।

नई व्यवस्था के तहत राशन कार्डधारकों के लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर का एक ही होना महत्वपूर्ण होगा। सरकार की ओर से राशन कार्डधारकों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने दोनों दस्तावेजों में दर्ज मोबाइल नंबर की जांच कर



लें। यदि आधार कार्ड और राशन कार्ड में अलग-अलग मोबाइल नंबर दर्ज हैं तो उन्हें एक समान करवा लें, ताकि डिजिटल राशन वितरण व्यवस्था लागू होने के बाद किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

दिल्ली में बड़ी संख्या में परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करते हैं। ऐसे में मोबाइल नंबर से संबंधित छोटी-सी लापरवाही भविष्य में

क्यों जरूरी है मोबाइल नंबर का एक जैसा होना ?

सीबीडीसी आधारित व्यवस्था में राशन वितरण को डिजिटल माध्यम से अधिक व्यवस्थित और सत्यापन योग्य बनाने की तैयारी है। ऐसे में लाभार्थी की पहचान और संबंधित डिजिटल प्रक्रिया में मोबाइल नंबर को महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसलिए सरकार चाहती है कि राशन कार्ड और आधार से संबंधित मोबाइल वितरण में किसी तरह का अंतर न रहे। सरकार से मिली जानकारी के अनुसार राशन कार्डधारक दो में से किसी एक तरीके से अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करा सकते हैं। जिसमें पहला विकल्प: राशन कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर को आधार कार्ड में अपडेट करा लें। दूसरा विकल्प: आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर को राशन कार्ड में अपडेट करा लें। यानी दोनों दस्तावेजों में एक ही मोबाइल नंबर पंजीकृत होना चाहिए।

राशन लेने की प्रक्रिया में परेशानी पैदा कर सकती है। खासकर ऐसे परिवार, जिनके मोबाइल नंबर हाल ही में बदले हैं या जिनके आधार और राशन कार्ड में अलग-अलग नंबर दर्ज हैं, उन्हें प्राथमिकता से अपना रिकॉर्ड जांच लेना चाहिए। सरकार की अपील है कि राशन कार्डधारक

आखिरी समय का इंतजार न करें और अपने दस्तावेजों में मोबाइल नंबर की स्थिति पहले ही जांच लें। इससे सीबीडीसी व्यवस्था लागू होने के बाद डिजिटल सत्यापन अथवा राशन प्राप्त करने की प्रक्रिया में अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकेगा।

हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव के लिए अपने केंद्रीय पैनल के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद शनिवार को चुनाव अभियान तेज कर दिया है। अध्यक्ष पद पर यश डबास, उपाध्यक्ष पद पर ईशू मौर्य, सचिव पद पर रिया छाबड़ी एवं संयुक्त सचिव पद पर लक्ष्यराज सिंह एबीवीपी के प्रत्याशी हैं।

चारों पदों पर जीत के लक्ष्य के साथ एबीवीपी कार्यकर्ता विभिन्न कॉलेजों, छात्रावासों एवं विद्यार्थी बहुल क्षेत्रों में लगातार संपर्क और संवाद कर रहे हैं। एबीवीपी पैनल से डूसू सचिव पद की प्रत्याशी रिया छाबड़ी ने कहा कि 'महिला सुरक्षा और हॉस्टल की सुविधा विद्यार्थियों की जरूरतें हैं। एबीवीपी ने इन मुद्दों को हमेशा जमीन पर उठाया है। हम चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्राओं को सुरक्षित माहौल मिले और हर विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई के



दौरान उचित और सुरक्षित आवास मिल सके। दावा करते हुए उन्होंने कहा कि एबीवीपी की मांग पर 2400 बिस्तर के गर्ल्स हॉस्टल का काम शुरू हुआ है, लेकिन विश्वविद्यालय में हॉस्टल की जरूरत इससे कहीं ज्यादा है। इसलिए आने वाले समय में

हॉस्टल की सीटें बढ़ाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। विद्यार्थियों के बीच एबीवीपी के पैनल को लेकर जो उत्साह दिख रहा है, उससे हमें पूरा विश्वास है कि इस बार डूसू में एबीवीपी 4-0 से जीत दर्ज करेगी।'

पीजी एवं छात्रावासों में विद्यार्थियों से किया संपर्क

शनिवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न पीजी एवं छात्रावासों में विद्यार्थियों से संपर्क कर विद्यार्थी हित से जुड़े मुद्दों पर संवाद किया। सत्य निकेतन हाउस के बाद चल रहे 'आखिर कब तक?' अभियान के तहत सुरक्षित विद्यार्थी आवास का मुद्दा उठाया गया। एबीवीपी की मांग और लगातार प्रदर्शनों के बाद 2400 बिस्तर के गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में हॉस्टल की सीमित संख्या और सीटों की कमी को देखते हुए सभी विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल की सीटें बढ़ाना और सुरक्षित एवं सुलभ आवास उपलब्ध कराना एबीवीपी का प्रमुख मुद्दा है।

गरीबों की झुग्गी बस्तियों को पर्दे से छिपाना भाजपा सरकार की विफलता: यादव

नई दिल्ली। दिल्ली में आयोजित हो रहे 18वें बिस्व शिक्षर सम्मेलन के दौरान विदेशी मेहमानों वाले प्रमुख आवागमन वाले मार्गों पर झुग्गी झोपड़ियों को पर्दों से छिपाना भाजपा सरकार की विफलता है। यह बात शनिवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कही। यादव ने कहा कि केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद जब भी दिल्ली किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम को मेजबानी करती है, तो गरीब आदमी सबसे ज्यादा पीड़ित होता है क्योंकि उनकी झुग्गी बस्तियों को पर्दे व अन्य संसाधनों से छिपाकर विदेशी मेहमानों को वास्तविकता से अलग दिल्ली का दोहरा स्वरूप दिखाया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रति मेहमान के भारत में मंडपन में आयोजित हो रहा बिस्व शिक्षर सम्मेलन तथा गरीबों का अपमान और असुविधाओं के अधीन जीवन जीते लोगों के प्रति अपवाद नहीं है। यादव ने कहा कि 12-13 सितंबर, 2026 को हो रहे 18वें बिस्व शिक्षर सम्मेलन से पहले, कई झुग्गी झोपड़ी समूहों और कम आय वाले गरीब लोगों को प्रमुख आवागमन वाले मार्गों के साथ बड़े नीले और सफेद या हरे रंग के पर्दे और कपड़े के पर्दे के पीछे छिपा दिया गया था। जिनमें वसंत विहार में कुली कैप बस्ती के आसपास सहित अन्य जगहों, जो केंद्र सरकार द्वारा राज्य स्तरीय राजनयिक कार्यक्रमों के दौरान शहरी असमंजस और गरीबों के प्रति भेदभाव की नीति को दर्शाता है।

‘दिल्ली मवन श्रमिक स्वास्थ्य योजना’ को मंजूरी

निर्माण श्रमिकों को मिलेगा दो लाख तक का इलाज : संघ

हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

दिल्ली में पंजीकृत भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रित परिवारों के लिए बड़ी राहत की योजना को मंजूरी मिल गई है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संघ ने 'दिल्ली भवन श्रमिक स्वास्थ्य योजना' को मंजूरी दे दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली मंत्रिमंडल इस योजना को मंजूरी दे चुके हैं। योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को इलाज के लिए आर्थिक परेशानी से बचाना है। इसके तहत प्रत्येक पंजीकृत निर्माण श्रमिक और उसके

प्राथी जीवनसाथी को 'हर साल स्वास्थ्य जांच' की सुविधा मिलेगी। योजना के तहत श्रमिक और पात्र परिवार के सदस्य सूचीबद्ध अस्पतालों में 'बिना नकद भुगतान के बाढ़ रोगी विभाग में डॉक्टर से परामर्श, जांच और दवाएं' ले सकेंगे। अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ने पर इलाज की सुविधा भी उपलब्ध होगी। ये सेवाएं 'केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की निर्धारित दर' पर उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार के अनुसार, प्रत्येक लाभार्थी को एक वर्ष में अधिकतम

इन बीमारियों और जरूरतों को भी किया शामिल

योजना में केवल सामान्य इलाज ही नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल किया गया है। इनमें 'आपातकालीन उपचार, काम के दौरान होने वाली बीमारियां, पुरानी बीमारियां, विशेष उपचार, मातृत्व स्वास्थ्य देखभाल और इलाज के बाद पुनर्वास' जैसी सुविधाएं शामिल हैं। निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना या अचानक चिकित्सकीय आपात स्थिति होने के बाढ़ रोगी विभाग में डॉक्टर से परामर्श, जांच और दवाएं' ले सकेंगे। अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ने पर इलाज की सुविधा भी उपलब्ध होगी। ये सेवाएं 'केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की निर्धारित दर' पर उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार के अनुसार, प्रत्येक लाभार्थी को एक वर्ष में अधिकतम

स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पर डॉक्टरों को देना होगा विशेष ध्यान: संघ

नई दिल्ली। 'उपचार, सशक्तीकरण और सम्मान' की भावना के अनुरूप महिलाओं के स्वास्थ्य को केवल जच्चा-बच्चा उपचार एवं देखभाल तक सीमित न रखकर व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना आवश्यक है। इसके लिए डॉक्टरों को बीमारियों की रोकथाम, समय पर पहचान, बेहतर उपचार, चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पर विशेष ध्यान देना होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संघ ने शनिवार को प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों के संगठन, एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट्स ऑफ दिल्ली के 48वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर यह बात साझा की। उन्होंने कहा कि कुत्रिम बुद्धिमत्ता, दूरचिकित्सा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और आधुनिक तकनीक का बेहतर उपयोग करके महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं की अधिक प्रमावी और सुलभ बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को उद्धृत करते हुए उपराज्यपाल संघ ने कहा कि 'नारी शक्ति राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार है।' उन्होंने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य में किया गया निवेश वास्तव में भारत की मानव पूंजी और देश के उज्ज्वल भविष्य में निवेश है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ महिला न केवल स्वस्थ परिवार की आधारशिला होती है, बल्कि एक सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र के निर्माण में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।



डेंगू से बचाव आसान है आपकी सतर्कता आपको और परिवार को डेंगू से बचा सकती है



डेंगू का मच्छर साफ रुक़े हुए पानी में पैदा होता है

मच्छर पैदा न होने दें		मच्छर के काटने से बचें	
	गमले, फूलदान या घर के आस-पास कहीं भी पानी जमा न होने दें।		कूलर के पानी को हर सप्ताह खाली करें या उसमें थोड़ा पेट्रोल/तेल डाल दें।
	पानी की टंकी, बाल्टी व अन्य बर्तनों को पूरी तरह ढक कर रखें।		अनुपयोगी कबाड़ जैसे कि टूटे बर्तन, बोतल, टायर और नारियल के खोल इत्यादि को खुले में न रखें/फेंके।
	पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें एवं मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें।		बुखार के समय घर व अस्पताल में मच्छरनाशी का नियमित इस्तेमाल करें।

डेंगू के लक्षण

	तेज बुखार		आंखों के पीछे तेज दर्द, जो आंखों के घुमाने से बढ़ता है		सर दर्द, मासपेशियों एवं जोड़ों में दर्द
	पेट दर्द		जी भिबलाना, उल्टी आना		शरीर पर दाने निकलना

उपरोक्त लक्षण दिखाई देने पर इलाज के लिए अपने निकटतम सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें

डेंगू की जांच व उपचार सभी सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध है					
For Any Queries, Please Contact : Name of DHOs with Contact Number & Zone (District)					
1. Dr. Hemant Kumar City SP (Old Delhi)	9990978034	5. Dr. V.N. Bhagat KPZ (Central North)	9717750141	9. Dr. Ajay Handa Shahdra-s (East)	9811015714
2. Dr. Nageshwar Marandi Central (South East)	9958001160	6. Dr. Madhuri Panth Narela (Outer North)	9958648615	10. Dr. Santosh Tomar Shahdra-s (North East)	9818579090
3. Dr. Sandeep Salve Civil Line (North)	8600598179	7. Dr. Vishal C. Soyam Najafgarh (South West)	9560945471	11. Dr. Deepak Mittal South (South)	8130698279
4. Dr. Aniket Sirohi KBZ (Central)	7217785459	8. Dr. Kanika Singh Rohini (North West)	9319733556	12. Dr. Ajay Kumar West (West)	9871663908

सौजन्य से : जल स्वास्थ्य विभाग दिल्ली नगर निगम

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवाएं निदेशावय, दिल्ली सरकार

PH-IV

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

खबर संक्षेप

दुकान से सोना व 3 लाख चोरी करने वाला अरेस्ट

फरीदाबाद। थाना एनआईडी क्षेत्र में ज्वेलरी पर हॉलमार्क करने वाली दुकान से 209 ग्राम सोना व 3



लाख रुपए नकद चोरी करने के मामले में थाना कोतवाली की टीम ने दुकान पर काम करने वाले आरोपी संतोष निवासी जिला सांगली महाराष्ट्र को पुणे महाराष्ट्र से 9 सितम्बर को गिरफ्तार कर तीन दिन पुलिस रिमांड पर लिया गया था। पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता दादासा यमगर निवासी एनआईटी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह मार्केट नंबर.1 में एचयूआईडी सेंटर चलाते हैं। आरोपी संतोष उनकी दुकान पर काम करता था तथा दुकान पर ही रहता था। दुकान व तिजोरी की चाबी भी उसके पास रहती थी। 4 सितंबर की रात दुकान बंद कर वह घर चले गए थे। संतोष का मोबाइल बंद मिला और दुकान के सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे। दुकान पर पहुंचने पर तिजोरी खुली मिली, जिसमें से 209 ग्राम सोना व 3 लाख रुपए नकद गायब थे।

एसके भारद्वाज भारी मतों से चुने गए प्रधान



फरीदाबाद। सेक्टर-12 स्थित जिला टैक्स बार एसोसिएशन फरीदाबाद के वर्ष 2026-27 के कार्यकारिणी चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। इसमें छह सीटों का चयन मतदान प्रक्रिया के द्वारा हुआ। कार्यकारिणी में एस. के. भारद्वाज भारी मतों से प्रधान चुने गए, इसके अतिरिक्त चेतन भारद्वाज सीनियर वाइस प्रेजिडेंट, एडवोकेट राजेश गुप्ता वाइस प्रेजिडेंट, सतेंद्र यादव महासचिव, सत्यवान नरवाल कैशियर एवं विनीत त्यागी संयुक्त सचिव के लिए चुने गए। पंजाब हरियाणा बार काउंसिल चंडीगढ़ के निर्देशानुसार महिला मॅंबर्स को कार्यकारिणी में शामिल किया गया, इसमें एडवोकेट मीनू कुमारी को वाइस प्रेसीडेंट फीमेल चुना गया। कार्यकारिणी सदस्यों में निखिल चौधरी, सोनिया सैनी एवं दिपांशु को निर्विरोध शामिल किया गया। सभी सदस्यों ने चुनाव अधिकारी नरेंद्र चौधरी का धन्यवाद किया। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करवाया। चुनाव अधिकारी नरेंद्र चौधरी के सहयोग के रूप में एडवोकेट दीपक गेरा एवं एडवोकेट संदीप मक्कड का धन्यवाद किया।

न्यायमूर्ति हरसिमरण सिंह सेठी के दिशा-निर्देशों पर राज्य भर में लोक अदालतों का आयोजन

हरिभूमि न्यूज ►► फरीदाबाद

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एकजीवकृत चेरमैन एवं न्यायमूर्ति पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़, हरसिमरण सिंह सेठी के दिशा निर्देशानुसार हरियाणा प्रांत में प्रत्येक जिले के अंदर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जिला फरीदाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं चेरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुधीर जीवन की अध्यक्षता एवं निर्देशानुसार तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जितेंद्र सिंह की देखरेख में आज जिला अदालत सेक्टर 12 फरीदाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

इस लोक अदालत में 19बंचे लगाए गए जिनमें सुधीर जीवन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कंवरपाल सिंह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अजय शर्मा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विनीत सजपा अतिरिक्त

बैठक में निगमायुक्त प्रदीप दहिया, अतिरिक्त निगमायुक्त यश जालुका समेत नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे

धर्मैट कौशिक ►► गुरुग्राम

गुरुग्राम में सड़क, सीवर, ड्रेनेज और जलापूर्ति से जुड़े विकास कार्यों को अब गति देने की तैयारी है। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्री राव नरबीर सिंह ने निगम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे हों और गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता न किया जाए। उन्होंने नगर निगम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर चल रहे, पूरे हो चुके और प्रस्तावित विकास कार्यों की जानकारी ली।

बैठक में बताया गया कि नगर निगम के वार्ड-1 से 18 तक विभिन्न विकास कार्यों पर करीब 366.40 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इनमें सड़क, सीवर, जलापूर्ति और जल निकासी से जुड़े कार्य प्रमुख हैं।



डिस्ट्रिक्ट गर्वनर लायन संदीप कुमार ने लॉयस क्लब फरीदाबाद ओल्ड की इंस्टालेशन सेरेमनी व 5 सदस्यों को दिलवाई शपथ

लायन सुरेश मदान बने प्रधान, लॉयस क्लब फरीदाबाद ओल्ड की इंस्टालेशन सेरेमनी में सदस्यों ने ली शपथ

» जनसेवा के कार्य करने व जरूरतमंदों के लिए बड़े प्रकल्प पर विचार करने का निर्णय किया

» दोहराया जरूरतमंदों की सेवा का संकल्प, शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया

» जनपद पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए

पदाधिकारियों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की

सभी ने उन्हें दिल से बधाईयां दी। क्लब में पांच स्थायी प्रकल्पों द्वारा प्रतिदिन सेवा कार्य किए जाने की सभी जनपद पदाधिकारियों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की। सर्व लायन आई.एस. कटारिया, राजपाल गर्ग, मुकेश अरोड़ा, राधेश्याम अग्रवाल, विनीत गर्ग, सचिव जयदीप कट्याल, रचना कात्याल, संजीव महाजन, जे.एम. मल्होत्रा, अशोक अरोड़ा, मुकेश गर्ग, राजेश शर्मा, रवि शर्मा, दिनेश गर्ग, धर्मेन्द्र कौशिक, सुभाष आहूजा सभी ने अपनी दी गई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। इस अवसर पर अन्य क्लबों के माननीय व विशिष्ट लायन सदस्यों बीएस शर्मा, नरगिस गुप्ता, एसके मंधोक, टीएस बेदी, योगेंद्र तेवतिया, महेश बांगा, संजीव वोकर, जेपी गुप्ता, आरके ओझा, आरके गोयल, जीके गुप्ता, आरपी ओझा, जेपी गुप्ता, संजीव गर्ग, प्रो.घु, राजन भट्टिया, सतीश परामनी, अनिल मेहता, गिरीश गुप्ता, प्रवीण रायव, शैलेन्द्र सिंघल राहुल सिंघल आदि ने अपनी गरिमायम उपस्थिति से समारोह की शोभा बढ़ाई।



मालाएं पहनाकर अभिनंदन किया। प्रधान लायन सुरेश मदान ने स्वर्ण जयंती वर्ष में बड़-चढ़कर जनसेवा के कार्य करने व जरूरतमंदों के लिए बड़े प्रकल्प पर विचार करने का निर्णय किया तथा अपने लायंस भवन सेक्टर-19 को मंदिर बताते हुए पीआरओ लायन प्रदीप गर्ग की क्लब के स्वर्ण जयंती वर्ष पर भावपूर्ण कविता को सराहा गया। एक्सेलेडर ऑफ गुडविल पूर्व गवर्नर लायन तेजपाल सिंह खिल्लन ने क्लब के कार्यों को सराहा व जनसेवा के बड़े कार्य करने को प्रोत्साहित किया व सहायता का आश्वासन भी दिया। वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डा. प्रतिभा

अग्रवाल व राकेश कुमार जगगी ने क्लब को शुभकामनाएं देते हुए उत्तम सेवा कार्य करते रहने को प्रोत्साहित किया। पूर्व गवर्नर लायन अनिल अरोड़ा ने सभी की ओर से क्लब को शुभाशीष व शुभकामनाएं दी।

क्लब के सदस्य लायन आर.एस. गांधी व लायन नरेश कुमार ने डिस्ट्रिक्ट लायन विद्यालय के छात्रों के लिए 50 हजार रुपए राशि की पुस्तकें दिलाने की घोषणा की। जनपद पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। पचास वर्ष पूर्व 14.6.77 को लायन ए.आर. वोहरा द्वारा इस क्लब की स्थापना की गई थी।

फरीदाबाद लोक अदालत में 1.31 लाख मामले रखे गए, 1.25 लाख से अधिक मामलों का आपसी सहमति से समाधान



प्रिसिपल जज फैमिली कोर्ट, रितु यादव अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सौरभ शर्मा जूडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमितेंद्र सिंह जूडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हिमानी जूडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिज्ञासा शर्मा जूडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोमल दहिया जूडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उपासना दहिया जूडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

जयोत्सना रावत न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, रजत कुमार कनौजिया न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वर्तिका मिश्रा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आनिया खिजरा अशरफ न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पंखुरी शुक्ला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, सारिका न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम, पारस चौधरी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, सरिता

सोलंकी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की बेंच बनाई गई जिनमें 131940 केस रखे गए जिनमे 125165 केसों का निपटारा, आपसी सहमति से लोक अदालत द्वारा किया गया जिनमें मोटर वाइकल दुर्घटना 52, छोटे-मोटे अपराधिक मामले 2564, चेक बाउंस 408, बिजली से संबंधित 872, समरी चालान 112850, वैवाहिक संबंधित 199, दीवानी 562, बैंक रिकवरी 3608, रेवेन्यू 4030, एग्जीक्यूशन 20 का निपटारा आपसी सहमति से किया गया। सीजेएम जितेंद्र सिंह ने बताया कि आज की लोक अदालत में लोगों का ट्रैफिक केसों को लेकर लोगों का रुझान रहा यानी की इस लोक अदालत में अधिक से अधिक ट्रैफिक चालान से संबंधित केसों का निपटारा किया गया। इस अवसर पर न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि लोक अदालत में फैसला होने पर जिसकी सुप्रीम कोर्ट तक कोई अपील नहीं होती कोर्ट फीस वापस हो जाती है तथा केस का फैसला हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है जिससे पैसे व समय की बचत होती है।

क्लीनिक में मरीजों की मेडिकल जांच, शीघ्र निदान और समय पर उपचार की सुविधाएं मुहैया कराई गईं

फोर्टिस एस्काॅट्रूस फरीदाबाद ने शीघ्र निदान और समय पर उपचार के लिए लॉन्च किया क्षेत्र का पहला फीवर क्लीनिक



से वेक्टर-जनित तथा वायरल संक्रमणों के कारण बुखार के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। यह फीवर क्लीनिक मौसमी वायरल इंफेक्शंस, डेंगू, मलेरिया,

चिकुनगुनिया, टायफाइड, इंप्लूएंजा, एनाएच1,अज्ञात कारणों या लंबे समय तक बने रहने वाले एक्यूट और संक्रामक रोगों के अलावा अन्य बैक्टीरिया जनित या संक्रामक कारणों समेत तथा इम्यूनोकोम्प्रोमाइज्ड मरीजों में बुखार के मामलों में उपचार प्रदान करेगा। मरीजों के लिए विस्तृत रूप से देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित करने के मकसद से, क्लीनिक में एक छत के नीचे सभी सेवाएं, जैसे फीवर कंसल्टेशन, स्पेशलाइज्ड लैब जांच जिनमें सीबीसी और पैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, फार्मसी तथा मेडिकेशन सर्पोट, डे-केयर एवं अन्य ऑब्जरवेशन सुविधाएं शामिल हैं, इमरजेंसी एस्केलेशन एवं हॉस्पिटल एडमिशन रेफरल्स और फालो.अप आदि उपलब्ध होगा। फीवर क्लीनिक के लॉन्च के मौके पर डॉ राजेश कुमार बुद्धिराजा, सीनियर डायरेक्टर, इंटरनल

मेडिसिन, फोर्टिस एस्काॅट्रूस हॉस्पीटल फरीदाबाद ने कहा कि मानसून और मौसम में बदलाव के समय, बुखार अलग-अलग कारणों से हो सकता है और समय पर रोगी का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण होता है। डॉ बी एन सिंह डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन, फोर्टिस एस्काॅट्रूस हॉस्पीटल फरीदाबाद ने कहा कि फीवर क्लीनिक का मकसद समय पर मूल्यांकन और प्रबंधन पर सही मेडिकल सलाह मिलने से हो सकता है, जबकि कुछ मरीजों को अधिक गहन ऑब्जरवेशन या हॉस्पीटल केयर की आवश्यकता होती है।

गुरुग्राम में विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार, राव नरबीर ने अधिकारियों को दिए समयबद्ध काम के निर्देश

अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए

मंत्री ने नगर निगम सीमा में चल रहे आरएमसी प्लांटों को बाहर करने की कार्रवाई करने और धनकोट मुख्य सड़क पर निर्माण से पहले अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है, ताकि सड़क बनने के बाद दोबारा खुदाई की स्थिति न आए।

जलभराव रोकने पर विशेष जोर

राव नरबीर सिंह ने सड़क निर्माण के दौरान रोड लेवल और आसपास की ड्रेनेज व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क और सीवर मैनहोल का स्तर सही रखा जाए, ताकि बारिश के दौरान जलभराव की समस्या न हो और वाहन चालकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक में वार्ड-9, 8,

16 और 4 में चल रहे स्टॉर्म वाटर ड्रेन के कार्यों की भी समीक्षा की गई। सेक्टर-9 और सेक्टर-9ए में करीब 12.57 करोड़ रुपए के जल निकासी कार्य चल रहे हैं। वार्ड-16 में उप्पल साउथएंड क्षेत्र को मास्टर ड्रेन से जोड़ने तथा वार्ड-9 में विभिन्न क्षेत्रों में ड्रेनेज व्यवस्था मजबूत करने के काम भी शामिल हैं।

सड़क और मॉडल रोड पर भी फोकस

वार्ड-15 में साउथ सिटी-2 निर्माण कंट्री और आसपास के क्षेत्रों में मॉडल रोड, फुटपाथ, ड्रेनेज और सड़क पुनर्निर्माण के कार्यों की भी समीक्षा हुई। इसके अलावा धनकोट, पलड़ा और बेगमपुर खटौला में सीवर और जलापूर्ति

से जुड़े कार्यों की भी गति देने के निर्देश दिए गए। बेगमपुर खटौला में 6.94 करोड़ रुपए की लागत से 2 एमएलडी एसटीपी का निर्माण हो रहा है, जिसका ट्रायल रन दिसंबर 2026 तक शुरू करने का लक्ष्य है।

पहल का उद्देश्य गुणवत्ता वाला आउटडोर एडवर्टाइजिंग ईको सिस्टम तैयार करना

नमो भारत कॉरिडोर पर साहिबाबाद से मोदीपुरम के बीच पियर और पोर्टल पर विज्ञापन के लिए निविदाएं बुलाई गईं



हरिभूमि न्यूज ►► गाजियाबाद

एनसीआरटीसी जल्द ही दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर साहिबाबाद से मोदीपुरम के बीच पियर्स और पोर्टल स्ट्रक्चर पर विज्ञापन कराएगा। इसके लिए पियर्स और पोर्टल स्ट्रक्चर पर विज्ञापन अधिकारों की लाइसेंसिंग हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। एनसीआरटी सी के पुनीत वत्स ने बताया कि नमो भारत कॉरिडोर गाजियाबाद और मेरठ के घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और व्यस्त बाजार वाले क्षेत्रों से होकर गुजरता है, विशेषकर इस निविदा के अंतर्गत प्रस्तावित 50 किलोमीटर से अधिक लंबे खंड पर। इसके साथ ही, कॉरिडोर उन प्रमुख हाईवे और मुख्य सड़कों के साथ-साथ भी गुजरता है जहाँ वाहनों की अत्यधिक आवाजाही बनी रहती है। वर्तमान में इस कॉरिडोर पर प्रतिदिन करीब 1.1 लाख यात्री यात्रा कर रहे हैं और इसने अब तक 4.5 करोड़ से अधिक कम्प्यूटर जर्नी का माइलस्टोन पर कर लिया है। यह नमो भारत पर लोगों के बढ़ते विश्वास के साथ ही यह दर्शाता है कि

यह इस क्षेत्र में तेजी से एक पसंदीदा परिवहन साधन के रूप में उभर रहा है। बढ़ती यात्री संख्या, रिहायशी, व्यावसायिक एवं बाजार क्षेत्रों के बीच कॉरिडोर की मौजूदगी और इसके साथ मौजूद सड़कों पर वाहनों की अधिक आवाजाही, पियर्स और पोर्टल पर उपलब्ध विज्ञापन स्थानों को आउटडोर कैपेन के लिए एक आकर्षक अवसर बनाते हैं। कॉरिडोर के पियर्स रणनीतिक रूप से सड़कों के मीडियन पर स्थित हैं। इससे इनपर दिए गए विज्ञापनों की बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सुनिश्चित होगी।

इस पहल का उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाला आउटडोर एडवर्टाइजिंग ईको-सिस्टम तैयार करना है, जो कॉरिडोर को देखने में आकर्षक बनाने के साथ-साथ गैर-क्रियाया राजस्व में भी योगदान देगा। साहिबाबाद से मोदीपुरम के बीच के इस खंड में कई औद्योगिक क्षेत्र, पियर्स पर विज्ञापन के लिए स्थान विकसित होने से इस मार्ग पर मौजूद व्यवसायों, स्कूल-कॉलेजों, रियल एस्टेट समूहों, अस्पतालों, एफ एंड बी चैन आदि के लिए यह एक प्रमुख ब्रांडिंग अवसर के रूप में उभर सकता है।

छत्तीसगढ़ के खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह बोले- खनन की अनुमति नहीं दी तारा कोल ब्लॉक पर भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों पर किया पलटवार

हरिभूमि न्यूज ►► गुरुग्राम

तारा कोल ब्लॉक को लेकर कांग्रेस नेताओं की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। यहाँ एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह ने कहा कि तारा कोल ब्लॉक के संबंध में कांग्रेस नेताओं द्वारा रखे जा रहे तथ्यों को पूरे संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जून 2021 में केंद्र सरकार से तारा कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम सीएमडीसी को आवंटित करने का आग्रह किया था। सौरभ सिंह ने कहा कि वर्तमान में तारा कोल ब्लॉक में खनन शुरू

करने की अनुमति नहीं दी गई है। भारत सरकार की वाणिज्यिक कोयला नीलामी में सीजी सिन-गैस एंड केमिकल्स लिमिटेड सफल बोलीदाता रही है। खनन शुरू होने से पहले वन स्वीकृति सहित सभी आवश्यक वैधानिक और पर्यावरणीय प्रक्रियाएं पूरी की जानी हैं। उन्होंने पेड़ों की कटाई को लेकर किए जा रहे दावों पर भी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि 10 लाख से अधिक पेड़ काटे जाने का दावा सही नहीं है। उनके अनुसार परियोजना में इससे काफी कम संख्या में पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है और यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होगी। सिंह ने कहा कि विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी सरकार की प्राथमिकता है।

10 आईफोन 12 सौ रुपए नगद बरामद हुए फर्जीवाड़ा कर ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले 2 काबू

हरिभूमि न्यूज ►► गाजियाबाद



थाना इन्दिरापुरम पुलिस ने क्रेडिट कार्ड के बिल जमा करने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले 02 उगों को गिरफ्तार किया है। उनकेकब्जे से 10 मोबाइल आईफोन, 01 बोट एयरपॉइस, 01 क्रोमा ईअरबड्स, 01फिलिप्स ट्रिंमर, 01 फिलिप्स गारमेन्ट्स स्टीमर, 01 पावर बैंक व 3 मोबाइल एंड्रॉयड व 12000 रू नगद बरामद हुए है। थाना इन्दिरापुरम पर एक महिला ने तहरीर दी थी कि युवकों द्वारा खुद को एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड डिपॉजिट कर्मचारी

बताकर एक्सिस बैंक के खाते से दो बार में करीब 3,12,589/- रुपए की राशि अनाधिकृत से ऑनलाइन फ्रॉड कर निकाल ली। जिसके संबंध में थाना इन्दिरापुरम पर तत्काल सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गई।

खबर संक्षेप

फौजी की मौत पर उठ रहे बड़े सवाल

रांची। झारखंड के कटकमसांडी प्रखंड क्षेत्र के छड़वा डैम स्थित जंगल में पेड़ से फंदे के सहारे सेना



के जवान का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान कंचनपुर गांव निवासी धनंजय कुमार देव (29), पिता राजकुमार देव के रूप में हुई है। धनंजय वर्ष 2016 में सेना में भर्ती हुआ था और वर्तमान में आर्मी में जवान के पद पर कार्यरत था। वह करीब एक माह की छुट्टी लेकर घर आया था।

छात्र नेता दिलीप दरभंगा से एमएलसी चुनाव लड़ेंगे

दरभंगा। बिहार के चर्चित छात्र नेता दिलीप कुमार ने आगामी विधान परिषद चुनाव में दरभंगा



स्नातक एमएलसी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर एमएलसी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से हुई कंभ्यूजन को भी दूर कर दिया है। दरअसल, राजद ने पटना स्नातक सीट से भी दिलीप कुमार नाम के कैडिडेट को टिकट दिया है।

बीएएमएस डॉक्टरों की भत्ता बढ़ाने की तैयारी

लखनऊ। सरकारी चिकित्सालयों में 7,500 रुपये मासिक भत्ते पर इंटरशिप कर रहे बीएएमएस



डॉक्टरों को अब 25 हजार रुपये मिलने की उम्मीद जगी है। आयुर्वेद सेवा निदेशालय ने भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों और चिकित्सालयों से इंटरन की संख्या और भत्ता बढ़ाने पर आने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार का पूरा व्योरा मांगा है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा ने किया एक अहम प्रयोग

मायावती की भतीजी दीपिका मिशान को आगे बढ़ाएंगी

एजेसी ►►लखनऊ

बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब भाई आनंद कुमार के बेटे नहीं बल्कि उनकी बेटी दीपिका आनंद बसपा के मिशन को आगे बढ़ाएंगी। मेरे लिए मिशन सर्वोपरि है,



लिहाजा अब मेरे भाई आनंद कुमार के बेटे नहीं, वकालत की पढ़ाई कर रही बेटी दीपिका आनंद पार्टी का कार्य करेंगी। आनंद जरूरत पड़ने पर अपनी जिम्मेदारियां उसे सौंप सकते हैं। आनंद दोनों बेटों को व युवा बच्चों में से किसी को भी जिम्मेदारी नहीं सौंपेंगे। बेटी के तैयार नहीं होने पर दलित वर्ग में से ही अन्य किसी मिशनरी कार्यकर्ता को भी अपनी यह जिम्मेदारी दे सकते हैं। आनंद के किसी भी बेटे को मौका नहीं दूँगे। बसपा में किसी भी छोटे-बड़े पद पर राजनीति करने का मौका नहीं दिया जाएगा।

ऐन एक का शेष

पहलगाम हमले के साथ ...

गई थी। इस हमले का बदला भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर नामक सैन्य कार्रवाई के जरिए लिया। जिसमें भारत-पाक नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार पाकिस्तान में छिपे बैठे 100 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था।

भारत से पश्चिम को गया ...

सामान्य बात है। खाड़ी के कई देश पश्चिम-एशिया युद्ध में आपस में लड़ रहे हैं, रूस भी युद्ध लड़ रहा है। लेकिन नई दिल्ली ने अपनी प्राथमिकता में शुमार शांति-स्थिरता की बात को जिस तरह से आम सहमति के साथ आगे बढ़ाया है। वह वाकई सराहनीय है। यह शांति न केवल भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए आवश्यक है। बल्कि इसका विश्व की भलाई के लिए भी बड़ा महत्व है।

शांति को धरातल पर जांचना जरूरी: विदेश मामलों के विशेषज्ञ डॉ. हेमंत अदलखा ने कहा कि बदलते वैश्विक माहौल और भारत-अमेरिका संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो दिल्ली में हो रहा ब्रिक्स सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह पश्चिम-एशिया से लेकर यूक्रेन तक युद्धों की जल्द समाप्ति के पक्ष में हैं। इन्हें खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन यहां मुख्य मुद्दा यह है कि

उत्तर प्रदेश के 57,600 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी

हरिभूमि न्यूज़ ►►लखनऊ

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर बच्चे को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पुस्तक ‘एग्जाम वॉरियर्स’ जरूर पढ़नी और आत्मसात करनी चाहिए। यह कहना अन्याय होगा कि युवा किताब नहीं पढ़ता, जरूरत किताबों को उन तक पहुंचाने की थी। ज्ञान को संकुचित दायरे में सीमित करने के दुष्परिणाम समाज और राष्ट्र, दोनों को भुगतने पड़ते हैं। 10 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश को ‘बीमारू’ राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया गया था। यूपी के

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर बच्चे को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पुस्तक ‘एग्जाम वॉरियर्स’ जरूर पढ़नी और आत्मसात करनी चाहिए। यह कहना अन्याय होगा कि युवा किताब नहीं पढ़ता, जरूरत किताबों को उन तक पहुंचाने की थी। ज्ञान को संकुचित दायरे में सीमित करने के दुष्परिणाम समाज और राष्ट्र, दोनों को भुगतने पड़ते हैं। 10 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश को ‘बीमारू’ राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया गया था। यूपी के



नौजवान के सामने पहचान का संकट था और नागरिक अपनी पहचान बताने से बचते थे। सकारात्मक प्रयासों के परिणामस्वरूप आज प्रदेश की तस्वीर बदली है। डिजिटल युग ने शहर और गांव की दूरी को कम किया है।

पहले संकुचित दायरे में बांधने का प्रयास किया गया मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी व्यक्ति की तरह ही समाज और राष्ट्र भी तब बीमार होता है, जब उसकी क्षमता समाप्त होने लगती है और वह अपनी विरासत से दूरी बनाने लगता है। पहले भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को संकुचित दायरे में बांधने का प्रयास किया गया, जिसके परिणाम सहने पड़े। उत्तर प्रदेश की धरती भारतीय ज्ञान परंपरा की महत्वपूर्ण केंद्र रही है।

सीएम ने विश्वविद्यालय परिसर में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित 5वें गोमती पुस्तक महोत्सव-2026 का शुभारंभ करने के उपरांत युवाओं को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सीएम ने वहां मौजूद बच्चों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पुस्तक ‘एग्जाम वॉरियर्स’ वितरित की। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। यह केवल स्कूली छात्रों के लिए नहीं, बल्कि हर युवा और नागरिकों के लिए भी उपयोगी है। जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी परीक्षा से गुजरना पड़ता है।

युवा किताब नहीं पढ़ता, यह कहना अन्याय

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कहना कि युवा पुस्तकों से दूर हो गया या सोशल मीडिया पर अपना समय खर्च कर रहा, पूरी तरह सही नहीं। ऐसा कहना युवा के साथ अन्याय होगा। जरूरत पुस्तकों को उसके पास पहुंचाने की व्यवस्था करने की है। जब पहली बार युवराज मलिक ने लखनऊ में पुस्तक महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था, तब मैंने तत्कालीन अपर मुख्य सचिव अमनीश अवस्थी से चर्चा की। इसे प्रोत्साहित करने की बात कही।

सम्राट सरकार का बड़ा फैसला

पेपर लीक रोकने के लिए 29 जिलों में परीक्षा भवन और स्ट्रॉन्ग रूम बनेंगे



एजेसी ►►पटना

बिहार में पेपर लीक और एग्जाम में कदाचार को रोकने के लिए 29 जिलों में परीक्षा भवन और स्ट्रॉन्ग रूम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस संबंध में बिहार बोर्ड यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) को निर्देश दे दिए हैं। सरकार ने 33 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। पहले चरण में 12 जिलों में परीक्षा भवन के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। इनमें सीतामढ़ी, लखीसराय, पूर्वी चंपारण, कैमूर, नालंदा, मधेपुरा जैसे जिले शामिल हैं।

आवश्यक सामग्री के सुरक्षित भंडारण की सुविधा

अधिकतर परीक्षा भवन और स्ट्रॉन्ग रूम को मौजूबा स्कूलों के परिसर में ही बनाया जाएगा। लगभग एक से डेढ़ एकड़ जमीन पर परीक्षा भवन के साथ स्ट्रॉन्ग रूम का निर्माण किया जाएगा। परीक्षा भवन में छात्र-छात्राओं के कदाचार मुक्त एग्जाम की सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। वहीं, स्ट्रॉन्ग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच एग्जाम के पेपर और आंसर शीट आदि को रखने की व्यवस्था होगी। सरकार का कहना है कि इससे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के पेपर एवं अन्य आवश्यक सामग्री के सुरक्षित भंडारण को सुविधा मिलेगी।

डीजी के साथ की तकनीकी गतिविधियों और अनुसंधान कार्यों की समीक्षा

जरूरतों के अनुरूप भारतीय रेल में तकनीकी विकास टी एन मिश्र ►►लखनऊ

टेस्टिंग लैब्स से लेकर ट्रैक मशीन सुविधाओं का किया गया निरीक्षण

रेलवे बोर्ड के सदस्य अवसरचन विवेक कुमार गुप्ता ने लखनऊ पहुंचकर अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) का दो दिवसीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आरडीएसओ में चल रही विभिन्न तकनीकी गतिविधियों और अवसरचन से जुड़े कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। डीजी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने भारतीय रेल की जरूरतों के अनुरूप तकनीकी विकास पर मंथन किया। इस दौरान गुप्ता ने आरडीएसओ की भू-तकनीकी, ट्रैक मशीन एवं मॉनिटरिंग, पुल एवं संरचना, धातु एवं रसायन, सिग्नल, एयर ब्रेक, इलेक्ट्रिक लोको



और फैटिंग टेस्टिंग प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने इन स्थानों पर उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं, परीक्षण क्षमता और मौजूदा अवसरचन की जानकारी ली। गुप्ता ने आरडीएसओ के महानिदेशक प्रमोद दनसाना और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की।

अनुसंधान और डिजिटल तकनीक पर जोर

विवेक कुमार गुप्ता ने आरडीएसओ की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की भी समीक्षा की। इस दौरान आरडीएसओ की ओर से प्रस्तुतीकरण दिया गया। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (क्रिस) और राइट्स (राइट्स) की ओर से इंस्पेक्शन पोर्टल के संबंध में भी जानकारी दी गई। इसमें निरीक्षण प्रक्रिया को अधिक मजबूत और व्यवस्थित बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया।

परिषदीय स्कूलों में चाइल्ड ट्रैकिंग के लिए 6.55 करोड़ जारी

यू-डायस प्लस के आंकड़ों से बच्चों की शैक्षिक स्थिति व नामांकन की होगी बेहतर निगरानी

हरिभूमि न्यूज़ ►►लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार परिषदीय विद्यालयों में बच्चों से जुड़ी सूचनाओं की निगरानी, विद्यालयी प्रबंधन और शैक्षिक व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में वर्ष 2026-27 के लिए एमआईएस (यू-डायस प्लस) और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के प्रभावी संचालन एवं उपयोग के लिए 6.55 करोड़ रुपये जारी किए जा रहे हैं। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी की ओर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को धराशि के उपयोग



और निगरानी के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ज्ञात हो कि इस व्यवस्था के माध्यम से योगी सरकार विद्यालयी आंकड़ों को अधिक व्यवस्थित, बच्चों की शैक्षिक प्रगति की निगरानी को अधिक प्रभावी तथा स्कूल

हर बच्चे की जानकारी को व्यवस्थित करने पर जोर

निर्देशों में यू-डायस प्लस पर विद्यालयों एवं विद्यालयों से संबंधित आंकड़ों के संकलन और उनके उपयोग को महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से बच्चों की शैक्षिक स्थिति पर नजर रखने की व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। पत्र में अपार आईडी और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के बीच समन्वय स्थापित करने की दिशा में भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट पहचान के साथ उसकी शैक्षिक जानकारी को व्यवस्थित रूप से ट्रैक किया जा सके।

खबर संक्षेप

कबड्डी में शामिल होने आया खिलाड़ी किशोर इबा, रेस्व्यू जारी

दुर्ग। जिले के उतई थाना क्षेत्र के सेलुदू भाठापारा स्थित तंदुला नहर में शनिवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। रायपुर के गुडियारी से सेलुदू में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल होने आए 15 वर्षीय खिलाड़ी शिवम यादव नहर के तेज बहाव में बह गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ को जानकारी दी गई। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर शिवम की तलाश में जुट गई है। जानकारों के अनुसार, शिवम यादव प्रतियोगिता स्थल के पास स्थित तंदुला नहर की ओर शौच के लिए गए थे। इसके बाद नहर किनारे हाथ-पैर धोने के दौरान काई और ढलान के कारण उनका पैर फिसल गया। नहर में पानी का बहाव तेज होने के कारण शिवम खुद को संभाल नहीं सके और गहरे पानी में बह गए। शिवम को नहर में बहता देखकर उनके साथी खिलाड़ियों ने तत्काल बचाने का प्रयास किया, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण वे सफल नहीं हो सके। देखते ही देखते शिवम तेज बहाव में लापता हो गए। घटना की सूचना सेलुदू सरपंच ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही उतई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल एसडीआरएफ को जानकारी दी। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्व्यू ऑपरेशन शुरू किया। फिलहाल टीम लगातार नहर में शिवम की तलाश कर रही है।

सेवा संकल्प अभियान को लेकर हुई चर्चा

भोपाल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल एवं प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में सेवा संकल्प अभियान की प्रदेश टोली एवं विभिन्न कार्यक्रमों की टोलियों की बैठक को संबोधित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक को प्रदेश शासन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं पाटी के प्रदेश हाहमंत्री व अभियान के प्रदेश संयोजक राहुल कोठारी ने भी संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश शासन के मंत्री राकेश सिंह, निर्मला भुरिया, विश्वास कैलाश सारंग, इन्दर सिंह परमार, कृष्णा गौर, धर्मेन्द्र सिंह लोधी, नरेन्द्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, राधा सिंह, प्रदेश महामंत्री लता वानखेडे, संभाग प्रभारी डॉ. अभय यादव सहित अन्य उपस्थित रहे।

कैरेटलेन ने कोलकाता के गरियाहाट में खोला नया फ्लैगशिप स्टोर

कोलकाता। भारत के प्रमुख ओम्नीचैनल ज्वेलरी ब्रांड्स में से एक, टाटा समूह के कैरेटलेन ने हाल ही में कोलकाता के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र, गरियाहाट में अपना नया फ्लैगशिप स्टोर लॉन्च किया। यह लॉन्च पूर्वी भारत में ब्रांड के रिटेल विस्तार की दिशा में एक और बड़ा कदम है। यह कैरेटलेन का महज एक और नया स्टोर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्टोर है जो दिखने में और अपने कलेक्शन में पूरी तरह से कोलकाता के रंग में रंगा हुआ है। इसके डिजाइन, सजावट, और माहौल में कोलकाता की अनूठी संस्कृति और यहां के लोगों की पसंद को झलक बेहद खूबसूरती से देखने को मिलती है। यह स्टोर कैरेटलेन के आधुनिक ज्वेलरी डिजाइन्स व



बेहतरीन ओम्नीचैनल शॉपिंग अनुभव को शहर के ग्राहकों के और करीब लाता है; जहाँ रोजमर्रा पहनने के लिए, उपहार और आभूषणों का कलेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। 3 मंजिलों का यह विशाल स्टोर पारंपरिक ‘कोल-ब्रेकिंग’ (कोयला तोड़ने की रस्म) के साथ शुरू हुआ, जो नए स्टोर की शुरुआत और आने वाले समृद्ध समय का प्रतीक माना जाता है। यह लॉन्च भारत के प्रमुख बाजारों में अपनी उपस्थिति को और

स्वास्थ्य मंत्री का बंगला घेरने का प्रयास, युवा कांग्रेस की पुलिस से झड़प

इलाज कराने वालों को होना पड़ रहा परेशान

मध्यप्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के निवास का घेराव करने की कोशिश की। प्रदेश अध्यक्ष यश लखन घनघोरिया ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाइट की भी हुई। युवा कांग्रेस अध्यक्ष यश लखन घनघोरिया ने आरोप लगाया कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और दवाइयों की कमी है। मरीजों को समय पर एंबुलेंस तक नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था की

स्वास्थ्य मंत्री पर जवाबदेही से बचने का आरोप



बदहाली के कारण आम लोगों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा है। घनघोरिया ने रीवा से लेकर भोपाल तक स्वास्थ्य सेवाओं

को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने ‘सेवा संकल्प अभियान’ को लेकर की पत्रकार वार्ता

हरिभूमि न्यूज़ ►► भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश भर में चलाए जाने वाले ‘सेवा संकल्प अभियान’ को लेकर शुक्रवार भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष सेवा, समर्पण, सुशासन और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हैं।

प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की इस सेवा यात्रा से जन-जन को परिचित कराने और सेवा के संस्कार को समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जा रहा है। यह केवल कार्यक्रमों की श्रृंखला नहीं, बल्कि सेवा, संस्कार, सुशासन और जनभागीदारी का व्यापक अभियान है। प्रधानमंत्री के सेवा-



संकल्प से प्रेरणा लेकर विकसित और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण को नई गति देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को धरातल पर उतारने का कार्य मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है। मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम के माध्यम से मध्यप्रदेश में दो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के विकास की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया है।

नवाचारों-आधुनिक तकनीकों पर केंद्रित प्रदर्शनी का सीएम ने किया शुभारंभ

महिलाओं की ओर से संचालित ‘रैपिडो पिक’ बाइक-टैक्सी को मिलेगा बढ़ावा

हरिभूमि न्यूज़ ►► भोपाल

मप्र में स्मार्ट, सुरक्षित, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार मोबिलिटी इकोसिस्टम के निर्माण में प्रदेश के नागरिकों, शोधकर्ताओं, शैक्षणिक संस्थानों और नवप्रवर्तकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर ‘एमपी मोबिलिटी इनोवेशन चैलेंज 2026’ का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में नवाचारों और आधुनिक तकनीकों पर केंद्रित विशेष प्रदर्शनी का शुभारंभ और अवलोकन भी किया।

मुख्यमंत्री का इंदौर के जनप्रतिनिधियों और बस ट्रांसपोर्ट संचालकों ने आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश में 14 सितंबर को विघ्नहर्ता भगवान गणेश का आगमन होने जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने गणेश स्थापना के माध्यम से देशवासियों को एकजुट किया था। इसी माह 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिवस है। उनके नेतृत्व में पहले गुजरात और अब भारत ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उनकी दूरदर्शी सोच से पूरा भारत गौरवान्वित है। मोदी सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले देश के इकलौते नेता हैं। देशभर से नक्सलवाद की समस्या खत्म हुई है। मप्र लाल सलाम को आधिरी सलाम करने वाला देश का पहला राज्य है।

◆ स्मार्ट और ग्रीन मोबिलिटी की ओर मध्यप्रदेश के कदम : इंदौर समिट में कनेक्टिविटी और नवाचारों पर हुआ मंथन



एमपीवायपी आईएल और रेपिडो के बीच एमओयू का आदान प्रदान हुआ।

◆ प्रदेश में सुरक्षित, सुलभ, किफायती और तकनीकी सक्षम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मिलेगी नई गति



एमपीवायपी आईएल और रेपिडो के बीच एमओयू का आदान प्रदान हुआ।

सीएम ने नवाचार और नवीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर केंद्रित प्रदर्शनी का शुभारंभ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में यात्री परिवहन विजन समिट-2026 के दौरान तकनीक, नवाचार और प्रदेश के नवीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने ब्रिलियंट कनेक्शन सेंटर में ही यात्री परिवहन विजन समिट-2026 में बस निर्माताओं, आईटी कंपनियों, वित्तीय संस्थानों एवं अन्य उद्योगों के साथ प्रदेश के विभिन्न शासकीय निर्माणों की गतिविधियों और नवाचारों पर आधारित इंडस्ट्री एक्सपो का भी उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एक्सपो में विभिन्न कंपनियों की ओर से प्रदर्शित बसों का अवलोकन किया तथा उनके फीचर्स और आधुनिक तकनीकी सुविधाओं की जानकारी ली। प्रदर्शनी में ट्रांसपोर्ट



नेटवर्किंग एवं एक्सपो का शुभारंभ किया।

सिस्टम परिवहन व्यवस्था को अधिक सुगम, सुरक्षित, आधुनिक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कई कंपनियों और संस्थानों ने सहभागिता की। प्रदर्शनी में कंपनियों ने अपनी तकनीक, सेवाओं, उत्पादों और नवाचारों का प्रदर्शन किया।

कर्मचारियों को पदोन्नति दुग्ध उत्पादन भी बढ़ाया

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में करीब एक लाख अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गई है। 85 हजार शासकीय पदों पर भर्तियां की जा रही हैं, जबकि ढाई लाख पदों पर आने वाले समय में भर्ती किए जाने की तैयारी है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और संकलन को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। निवेश और रोजगार के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

71 हजार से अधिक बूथों के लाभार्थियों तक पहुंचेगी भाजपा: खंडेलवाल

प्रदेश अध्यक्ष खण्डेलवाल ने कहा कि पीएम मोदी के सेवा व समर्पण के 25 वर्ष जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जाएगा। भाजपा ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिए 71 हजार से अधिक बूथों के लाभार्थियों तक पहुंचेगी। 17

सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 17 सितंबर को शाम सात बजे प्रदेश के 71 हजार से अधिक बूथों के हर लाभार्थियों के घरों में आशीर्वाद का दीया प्रज्वलित किया जाएगा। 07 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं।

प्रदेश के सभी 11404 शक्ति केंद्रों पर सेवा की कहानियां करेंगे साझा

खण्डेलवाल ने कहा कि प्रदेश के सभी 11404 शक्ति केंद्रों में सेवा की कहानी कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के लाभार्थियों की न्यूनतम 10-10 वास्तविक कहानियों (रीलस) को सोशल मीडिया पर साझा किया जाएगा। 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हर जिले और गांव में

पदयात्रा, साइकिल व बाइक रैलियां निकाली जाएंगी, जो एक मुख्य स्थल पर मिलकर ‘विकसित भारत-2047’ का सामूहिक संकल्प लेगी। गुजरात के चडवनगर स्थित हाटकेश्वर महादेव का जलमिषेक कर 250 बाइकों पर 500 यारी जल लेंटर वाराणसी (काशी विश्वनाथ) के लिए 10 अलग-अलग समूह में प्रस्थान करेंगे।

प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने की समीक्षा

‘जन विश्वास अभियान’ में डोर-टू-डोर सर्वे कर शिकायतों का करें निराकरण

हरिभूमि न्यूज़ ►► भोपाल

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने बैतुल वृत्त का मैदानी दौरा कर विद्युत वितरण व्यवस्था, राजस्व संग्रहण, अधोसंरचना विकास कार्यों एवं उपभोक्ता सेवाओं की समीक्षा की।

इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही कंपनी के राजस्व में सुधार के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गर्ग ने जन विश्वास अभियान की तैयारियों और कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि शिविरों से पहले क्षेत्र में डोर-टू-डोर सर्वे किया जाए। सर्वे के दौरान उपभोक्ताओं की मोटर, बिलिंग एवं अन्य विद्युत संबंधी समस्याओं की जानकारी एकत्र कर उनका शिविरों में प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित किया जाए।



राजस्व संग्रहण की समीक्षा करते हुए प्रबंध संचालक ने अधिक बकाया वाले क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण में लापरवाही या असंतोषजनक कार्य प्रदर्शन पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा के दौरान उन्होंने लाइनों एवं ट्रांसफार्मरों के नियमित रख-रखाव, लाइन पेटोलिंग तथा विद्युत लाइनों के आसपास पेड़ों की शाखाओं की समय पर कटाई-छंटआई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मिरे असेट एमएफ ने बीएसई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडेक्स फंड लॉन्च किया

मुंबई। मिरे असेट कन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मिरे असेट बीएसई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडेक्स फंड बीएसई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टोटल रिटर्न इंडेक्स को रैलिफेड/ट्रेक करने वाली एक ओपन-एंडेड स्कैमि के लॉन्च की घोषणा की है। यह फंड निवेशकों को एक ही इंडेक्स-ट्रेकिंग प्रोडक्ट के जरिए भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैसिव और रूल्स-बेस्ड तरीके से निवेश का मौका देता है। इस सेक्टर में आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, आईटी-इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और हार्डवेयर कंपनियां शामिल हैं। इस फंड का नया फंड ऑफर एनएफओ 8 सितंबर को खुलेगा। 22 सितंबर को बंद होगा। इसके बाद यह स्कैमि निरंतर बिक्री और पुनर्वर्तित सेल एंड री-परचेज के लिए 28 सितंबर को फिर से खुलेगी। मिरे असेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ईटीएफ प्रोडक्ट्स के प्रमुख और फंड मैनेजर सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने कहा भारत का आईटी सेक्टर डॉट कॉम कैश से लेकर कोविड-19 तक कई टेक्नोलॉजी साइकिल की कमीटी पर परखा जा चुका है और हर बार यह इंडस्ट्री खुद को ढालकर और भी मजबूत होकर उमरी है।

हांसी में 3 हरियाणा बटालियन एनसीसी का प्रशिक्षण शिविर



हांसी। द ईई कॉलेज, घड़ी, हांसी में 3 हरियाणा बटालियन एनसीसी, हिसार के तत्वाधान में वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर का आयोजन बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सुनील कटारिया के नेतृत्व में किया जा रहा है। 12 से 21 सितंबर तक चलने वाले इस वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से कुल 590 एनसीसी कैडेट्स उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। शिविर में कैडेट्स को अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, शारीरिक दक्षता, डिल, मानचित्र-पठन, हथियार प्रशिक्षण,

व्यक्तित्व विकास तथा राष्ट्र सेवा से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। विशेष रूप से, रोहतक ग्रुप के अंतर्गत 11 बटालियनों से 194 आरडीसी कैडेट्स भी इस शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। इन कैडेट्स को आगामी रिपब्लिक डे कैप (आरडीसी) की तैयारियों के दृष्टिगत विभिन्न सैन्य एवं सशस्त्र-युद्ध गतिविधियों में दक्ष बनाया जाएगा। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कटारिया ने कैडेट्स को शिविर के दौरान अनुशासन, समर्पण और टीम भावना के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।

संतोषी विहार में 1.43 करोड़ के विकास कार्यों को मिली रफ्तार

भोपाल। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के बाद 68 में विकास कार्यों को गति देते हुए विधायक एवं मंत्री कृष्णा गौर ने विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। करीब 1.43 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले इन विकास कार्यों की कड़ी में संतोषी बिहार कॉलोनी स्थित मंदिर में पेंथिंग ब्लॉक लगाने, मंदिर की छत के सुधार तथा सामने की मुख्य सड़क के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद कॉलोनी के प्रमुख उमेश गौतम एवं मंजू गौतम के निवास पर मंत्री कृष्णा गौर का शाल ओढ़कर सम्मान किया गया। इस दौरान क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों ने अपनी बात भी रखी। कार्यक्रम में क्षेत्रीय पापंद उर्मिला मौर्य, जिला उपाध्यक्ष भीमक सिंह बघेल, इंदरपुरी मंडल अध्यक्ष लतकुरु यादव, पापंद वाई शिरोमणी शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निमाता-निर्देशक मंजू उमेश गौतम, लक्ष्मी ठाकुर, कॉलोनी अध्यक्ष वीरेंद्र निपाठी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

भारत व कनाडा में रणनीतिक साझेदारी की घोषणा

नई दिल्ली। भारत की सॉवरनेन एआई क्लउड सेवा प्रदाता भारथक्लाउड ने भविष्य की बांड मार्केटिंग पहलों और इवेंट टेक्नोलॉजी के लिए उत्तरी अमेरिका और भारत में परियोजना करने वाली एआई-संचालित प्रोद्योगिकी कंपनी आइडेंटोस के साथ साझेदारी की है। यह ऐसे समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब एमएएसएमई भारत की जीडीपी में 31.1 प्रतिशत का योगदान कर रहे हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा मंत्रियों ने वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार में मजबूत वृद्धि का उल्लेख किया, जो 2024 में 23.66 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें वस्तु व्यापार का मूल्य लगभग 8.98 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है।

इनडीड हायरिंग इंडेक्स जारी, कैडिडेट्स ने पारदर्शिता की मांग की

नई दिल्ली। हायरिंग की प्रक्रिया में लगातार बढ़ावा हो रहा है। जांब मैनिंग और हायरिंग में ग्लोबल लीडर, इनडीड ने हायरिंग के सफर में दोनों पक्षों की स्थिति को स्पष्ट करने का अद्वितीय नजरिया पेश किया है। कंपनी का नया हायरिंग कॉन्फिडेंस इंडेक्स यह समझने में मदद करता है कि हायरिंग प्रक्रिया में विश्वास कैसे स्थापित होता है, कहां पर आक्षेप पूरी नहीं हो पा रही है और एम्प्लॉयर कैडिडेट्स को हायरिंग का ज्यादा स्पष्ट, निष्पक्ष और मानवीय अनुभव कैसे प्रदान कर सकते हैं। कैडिडेट हायरिंग की प्रक्रिया में एम्प्लॉयर से ज्यादा स्पष्टता चाहते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर की उम्मीद पूरी नहीं हो पाती है। इनडीड के पहले हायरिंग कॉन्फिडेंस इंडेक्स मेजरिंग जांब सेंसर कॉन्फिडेंस इन हायरिंग एंड एआई के मुताबिक भारत की 100 में से 58 का स्कोर मिला है। इनडीड ने हायरिंग कॉन्फिडेंस इंडेक्स यह समझने के लिए पेश किया है कि हायरिंग की प्रक्रिया में कैडिडेट का विश्वास बढ़ाने या घटाने वाली चीजें कौन सी हैं। इसमें नौकरी के इन्सुकों और एम्प्लॉयर, दोनों के जवाबदेही को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में हायरिंग के उन दैनिक पहलुओं को शामिल किया गया है, जो विश्वास बढ़ाते हैं। इनमें काम को लेकर स्पष्टता, हायरिंग की समय सीमा, रिफ्यूट के साथ धार्तव्य, कैडिडेट का मूल्यांकन करने का तरीका और एआई का उपयोग शामिल है। रोहन सिक्केट्टर, टैलेट स्ट्रैटजी एक्जिक्यूटिव, इनडीड ने कहा नौकरी तलाश रहे कैडिडेट्स की अपने आवेदन को लेकर अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए। नौकरी के बाजार में विश्वास कैसे स्थापित होता है, यह समझने के लिए इनडीड ने पहला ट्रस्ट हायरिंग इंडेक्स पेश किया है, जिसमें भारत को कैडिडेट्स के ट्रस्ट के लिए 100 में से 58 का बेसलाईन स्कोर प्राप्त हुआ है।

राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन में जर्जर इमारत ढहने की घटना कोई अकेली त्रासदी नहीं है, बल्कि यह भारत की बढहाल शहरी बुनियादी संरचना और जर्जर इमारतों के उस विशाल संकट का एक ख़ौफनाक प्रतीक है, जहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी, अवैध निर्माण और प्रशासन की घोर लापरवाही इंसानी जिंदगियों पर भारी पड़ रही है। एक तरह शहरों में तब्दील हो रहे गांव और उनमें बढती आबादी के ज़रूरत अनुसार तमाम सुविधाएं जुटाने और सुरक्षा मुहैया कराने में प्रशासन और स्थानीय निकाय सुस्त पड़े हैं। वहीं किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय न होना भी इस समस्या को और विराल रूप दे रही है। शहरों को स्मार्ट बनाने का अर्थ केवल कैमरे, ऐप और डिजिटल सिस्टम लगाना नहीं है। स्मार्ट शहर वह है, जहां नागरिक को साफ सड़क, सुरक्षित फुटपाथ, व्यवस्थित यातायात, पर्याप्त पानी, बेहतर सीवर, स्वच्छ वातावरण और समय पर सरकारी सेवाएं मिलें। इसके लिए सरकार को शहरी प्रशासन का विकेंद्रीकरण, स्थानीय निकायों को पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और नागरिकों के प्रति स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। अब समय केवल शहरों को फैलाने का नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर तरीके से संचालित करने का है। *इन्हीं मुद्दों की पड़ताल करता आजकल का यह खास अंक...*

बढ़ती आबादी और सुस्त स्थानीय निकाय



विस्लेषण

उमेश चतुर्वेदी

वरिष्ठ स्तंभकार

शहरी नियोजन और उसकी चुनौतियों को समझने से पहले शहरी इलाकों में रह रही जनसंख्या और शहरों की ओर बढ़ती ललक के आंकड़ों पर ध्यान देना जरूरी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी देश की कुल जनसंख्या का 31.16 प्रतिशत यानी करीब 37.71 करोड़ थी। हालिया अनुमानों के अनुसार, यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 36 प्रतिशत के आसपास पहुंच गया है। 1981 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक देश की शहरी आबादी 15.9 करोड़ और तब की आबादी का 23.3 प्रतिशत थी। साफ है कि भारत में शहरीकरण या शहरों की ओर पलायन अस्सी के दशक में बढ़ गया था, जिसमें नई आर्थिक नीति के बाद तेजी दिख रही है।

शिक्षक दिवस के अगले ही दिन दिल्ली के सत्य निकेतन की एक इमारत के जमींदोज होने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने भारत की शहरी आबादी की सुरक्षा, सहूलियतों और सुविधाओं पर सवाल खड़ा कर दिया है। भारत की सदियों से पहचान उसकी ग्राम और कृषि संस्कृति के लिए रही है। लेकिन आधुनिक आर्थिकी को अपनाने के बाद भारत अपनी इस पहचान को लगातार पीछे छोड़ने की कोशिश में जुटा है। पश्चिम की तरह वह भी शहरीकरण को विकास का मानदंड मान चुका है। देश की बड़ी आबादी कभी मजबूरी के रोजगार तो कभी शिक्षा तो कभी स्वास्थ्य कारणों से लगातार शहरों की ओर पलायन कर रही है। पलायन की इस प्रवृत्ति को प्रतिशत के लिहाज से देखें तो बड़ी भले न लगे, लेकिन विशाल जनसंख्या वाले देश के लिहाज से असल में यह संख्या बहुत बड़ी है। इसका असर शहरी नियोजन और प्रशासन पर भी रोजना दिखता है।

आंकड़ों की बाजीगरी में इस दबाव की लगातार अनदेखी होती रहती है। इस खेल में शहरी इलाकों में रहने वाली जनसंख्या और उन्हें मिलने वाले छोटे और किसी तरह पेट भर पाने वाले रोजगार को ही विकास का पैमाना मान लिया जाता है। सत्य निकेतन की घटना ने आंकड़ों की इसी बाजीगरी और शहरी नियोजन के साथ ही शहरी निकाय प्रबंधन के बारे में सोचने का अवसर मुहैया कराया है। शहरी नियोजन और उसकी चुनौतियों को समझने से पहले शहरी इलाकों में रह रही जनसंख्या और शहरों की ओर बढ़ती ललक के आंकड़ों पर ध्यान देना जरूरी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी देश की कुल जनसंख्या का 31.16 प्रतिशत यानी करीब 37.71 करोड़ थी। हालिया अनुमानों के अनुसार, यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 36 प्रतिशत के आसपास पहुंच गया है। 1981 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक देश की शहरी आबादी 15.9 करोड़ और तब की आबादी का 23.3 प्रतिशत थी। साफ है कि भारत में शहरीकरण या शहरों की ओर पलायन अस्सी के दशक में बढ़ गया था, जिसमें नई आर्थिक नीति के बाद तेजी दिख रही है।

शहरों की ओर पलायन

संयुक्त राष्ट्र-हैबिटेट के वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2016 के आकलन के मुताबिक भारत की शहरी आबादी 2015 में 42 करोड़ थी। कुछ अनुमानों के अनुसार, साल 2030 तक भारत की 40 फीसद से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगी, जबकि कुछ अनुमानों में इसे पचास प्रतिशत तक बताया जा रहा है। अगर मौजूदा आंकड़ों के अनुसार मान लें कि करीब 40 फीसद ही आबादी शहरों में रह रही है तो एक सौ पचास करोड़ की जनसंख्या के लिहाज से यह संख्या सात करोड़ के आसपास बैठती है। यह संख्या अकेले अमेरिका की जनसंख्या से दोगुनी है। लेकिन अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो भारत की स्थिति अमेरिका के मुकाबले बेहद कम है। इसलिए उसकी बराबरी कम से कम मौजूदा हालात में संभव नहीं है।

उदारीकरण की जिस मौजूदा आर्थिकी को पूरी दुनिया ने अपना रखा है, वह अमेरिका और ब्रिटेन से आई है। इस लिहाज से देखें तो मौजूदा आर्थिकी के प्रभाव में पूरी दुनिया अमेरिका होना चाहती है, लेकिन संसाधनों के संदर्भ में देखें तो ऐसा होना तत्काल संभव नहीं है।



अवैध मकान बनाने की प्रवृत्ति पर लगाम नहीं

नगर निगम और पुलिस वालों में इतना सहयोग दिखता है कि अगर एक किसी नए निर्माण को सूचना से वंचित रह गया तो दूसरा अपना हिस्सा लेने के बाद उसे सुचित जरूर करता है, ताकि बेईमानी की इस कमाई में आपसी ईमान बना रहे। दिल्ली ही नहीं, देश के तमाम राज्यों में स्थानीय स्तर पर कई गांव भी शहरों में समा गए हैं। लेकिन उनके प्रशासन और नियोजन के लिए स्थानीय निकायों में उस तरह की दिलचस्पी नहीं देखी जाती, जैसी विकसित कॉलोनियों और पोंश मोहल्लों के लिए दिखती है। एक यह भी कारण है कि सत्यनिकेतन की बिल्डिंग जैसे कमजोर और अवैध मकान बनाने की प्रवृत्ति पर लगाम नहीं लगा सकती। दो राय नहीं

कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय निकायों की वित्तीय और दूसरे अधिकार तो मिले ही हैं, उनके लिए आवंटन भी बढ़ा। लेकिन उन्हें जैसी चुस्की दिखायी चाहिए, वह उनमें नहीं दिखती। एक बात और है कि शहरी निकाय प्रशासन की कल्पना शक्ति जैसी होनी चाहिए, नजर नहीं आती। इसलिए विकास की दिशा को लेकर वे सचेत नहीं दिखते। सत्यनिकेतन की घटना के बहाने शहरी निकाय प्रशासन की इन चुनौतियों पर खुला विमर्श होना चाहिए, तभी राह निकलेगी और संभव है देश के शहर भी अमेरिकी-यूरोपीय शहरों की तरह साफ, चमकीले और नागरिक सुविधाओं से युक्त बन सकेंगे।

उचित सुविधाएं जुटाना कठिन

अमेरिका या यूरोप की तरह शहरों में बसना आज प्राथमिकता हो गई है, सरकारें भी चाहती हैं कि गांवों की तुलना में शहर ही ज्यादा हों। इसकी वजह यह है कि शहरी जनसंख्या और रियायत एग्री होती है, ग्रामीण आबादी की तरह बिखरी नहीं होती। इसकी वजह से बिजली और परिवहन जैसी सुविधाएं गांवों की तुलना में शहरी आबादी को कहीं ज्यादा आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती है। इस प्रक्रिया में हो ये रहा है कि बेतहाशा बढ़ती शहरी आबादी के लिए उचित सुविधाएं जुटाना ना तो सरकारों के लिए आसान है और ना ही शहरी प्रबंधन की जवाबदेही वाले स्थानीय निकाय ही। रहीं बात शहर आने वाले लोगों की तो उनमें बड़ी संख्या कुछ हजार महीने कमाने वालों की है। अपनी छोटी कमाई से वे किसी तरह गुजर-बसर ही करते हैं। शहरों की बड़ी आबादी इसी वजह से सस्ते या कई बार दड़बेनुमा सीलनमरे मकानों और कमरे में ही जिंदगी गुजारने को मजबूर है। कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के सामने भी कुछ वैसी ही चुनौतियां हैं। सत्यनिकेतन में मारे गए छात्रों में से ज्यादातर ऐसी ही पृष्ठभूमि से थे।

छात्रावासों की गिनगानी जरूरी

मौजूदा अर्थव्यवस्था के चलते किसी भी राज्य या शहरी निकाय प्रशासन और सरकार के लिए संभव ही नहीं है कि हर व्यक्ति को साफ और उचित घर मुहैया करा सके। केंद्र सरकार के भी वश का नहीं कि हर छात्र को वह स्वच्छ और सहूलियत युक्त छात्रावास और कमजोर आर्थिक आय वाले व्यक्ति को मकान उपलब्ध करा सके। लेकिन सरकारें एक काम जरूर कर सकती हैं। खुले बाजार में उचित दर पर सहूलियत भरे मकान उपलब्ध कराने वाले मकान मालिकों और छात्रावास संचालकों की गिनगानी जरूर कर सकती है, लेकिन ऐसा होना नहीं। स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकायों के जवाबदेह ज्यादातर लोगों की गिनाह ऊपरी कमाई पर होती है। दिल्ली के लोगों को पता है कि वे अगर घर बनाना शुरू करते हैं तो नगर निगम का स्थानीय बेलदार मकान मालिक से वसूलने में देर नहीं लगाता। कानूनी रूप से अब दिल्ली पुलिस की भूमिका इन मामलों में खल कर दी गई है। लेकिन अब भी स्थानीय और बीट कॉन्स्टेबल भी निर्माण कार्यों के पंचज में वसूली करते हैं।

निकायों की जवाबदेही तय करने का समय



व्यवस्था

योगेश कुमार सोनी

स्वतंत्र पत्रकार

परिवर्तन संसार का नियम है। तरक्की करना व्यक्ति व देश की अनिवार्यता है, लेकिन इसके चलते साइड इफेक्ट का भी ध्यान रखना जरूरी है। भारत तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। गांवों और कस्बों से शहरों की ओर बढ़ती आबादी ने महानगरों पर भारी दबाव पैदा कर दिया है। सड़कें पहले से अधिक व्यस्त हैं, सीवर व्यवस्था पर बोझ बढ़ रहा है, पेयजल की मांग बढ़ रही है और कचरा प्रबंधन जैसी समस्याएं लगातार गंभीर होती जा रही हैं। इसके बावजूद हमारी शहरी व्यवस्था आज भी काफी हद तक पुराने ढंग पर चल रही है। ख़याल यह है कि क्या केवल नई सड़कें, प्लाईओवर और कुछ बड़ी परियोजनाएं बनाकर शहरों को बेहतर बनाया जा सकता है? शायद नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि स्थानीय निकायों और शहरी प्रशासन के पूरे ढांचे की समीक्षा की जाए। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत नागरिकों के सबसे नजदीक की सरकार हैं। नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी अधिकतर समस्याएं इन्हीं संस्थाओं से संबंधित होती हैं- सड़क, नाली, सीवर, कूड़ा, स्ट्रीट लाइट, पार्क, पार्किंग और स्थानीय स्तर की स्वच्छता। लेकिन समस्या यह है कि कई बार जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की होती है, जबकि निर्णय लेने और धन उपलब्ध कराने की शक्ति किसी दूसरे स्तर पर होती है। परिणामस्वरूप नागरिक विभागों के बीच चक्कर लगाता रहता है। इस व्यवस्था में बदलाव जरूरी है। जिस संस्था को जिम्मेदारी दी जाए, उसे पर्याप्त अधिकार और वित्तीय संसाधन भी दिए जाने चाहिए। सड़क बने और कुछ दिन बाद फिर खोद दी जाए। हमारे शहरों की एक बड़ी समस्या विभागों के बीच समन्वय की कमी है। एक एजेंसी सड़क बनाती है, कुछ समय बाद सीवर या पानी की पाइपलाइन के लिए सड़क खोद दी जाती है। फिर किसी अन्य एजेंसी द्वारा केबल या पाइपलाइन डालने के लिए वही सड़क दोबारा खोदी जाती है। इससे सरकारी धन की बर्बादी तो होती ही है, नागरिकों को भी धूल, जान, दुर्घटना और जलमाराव जैसी परिश्रानियां झेलनी पड़ती हैं। इसका समाधान एकीकृत शहरी योजना में है। सड़क निर्माण से पहले यह तय होना चाहिए कि अगले कई वर्षों में उस सड़क के नीचे किन-किन सेवाओं की जरूरत पड़ेगी। नागरिक केवल करदाता नहीं, भागीदार भी हैं। शहर में रहने वाला नागरिक केवल संपत्ति कर, पानी का बिल या अन्य शुल्क देने वाला व्यक्ति नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसे यह जानने का अधिकार भी है कि उसके क्षेत्र के विकास के लिए किना धन आया, कहाँ खर्च हुआ और काम की गुणवत्ता कैसी रही। सूचना का अधिकार नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड और परियोजनाओं से संबंधित जानकारी हासिल करने का महत्वपूर्ण माध्यम देता है। इसी तरह शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था नागरिकों को अपनी समस्याएं संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का रास्ता देती है। लेकिन अधिकार तभी प्रभावी होगा जब शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई भी हो। यदि किसी इलाके में महीनों से सड़क टूटी हुई है, नाली जाम है या जलमाराव लगातार हो रहा है, तो नागरिक को यह पता होना चाहिए कि इसके लिए जिम्मेदार विभाग कौन है और समाधान की समयसीमा क्या है। आज जरूरत ऐसी व्यवस्था है जो जिसमें हर शिकायत का एक जिम्मेदार अधिकारी, निश्चित समयसीमा और कार्रवाई की स्थिति नागरिक को दिखाई दे। इसके साथ ही नगर निकायों के बजट और परियोजनाओं को अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। जनता को यह जानकारी आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए कि उसके वार्ड में किना पैसा स्वीकृत हुआ और उसका उपयोग कहाँ किया गया। वार्ड स्तर पर बड़े नागरिकों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। शहरी प्रशासन को केवल अधिकारियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। वार्ड समितियों और स्थानीय नागरिक समूहों को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। मोहल्ले के लोगों को यह बताने का अवसर मिलना चाहिए कि उनके क्षेत्र की प्राथमिक जरूरत क्या है। कहीं सड़क की जरूरत है, कहीं पार्क की, कहीं पार्किंग की और कहीं पानी निकासी की। हर इलाके की समस्या एक जैसी नहीं होती। इसलिए स्थानीय जरूरतों के आधार पर स्थानीय योजनाएं बनाना अधिक प्रभावी होगा। शहरों का भविष्य केवल सरकार नहीं, नागरिक भी तय करेंगे। शहरों को स्मार्ट बनाने का अर्थ केवल कैमरे, ऐप और डिजिटल सिस्टम लगाना नहीं है। स्मार्ट शहर वह है जहां नागरिक को साफ सड़क, सुरक्षित फुटपाथ, व्यवस्थित यातायात, पर्याप्त पानी, बेहतर सीवर, स्वच्छ वातावरण और समय पर सरकारी सेवाएं मिलें। इसके लिए सरकार को शहरी प्रशासन का विकेंद्रीकरण, स्थानीय निकायों को पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और नागरिकों के प्रति स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। आखिरकार शहर किसी एक सरकार या विभाग के नहीं होते। शहर वह रहने वाले नागरिकों के हो जाते हैं। इसलिए शहरी विकास की हर योजना के केंद्र में नागरिक होना चाहिए। यदि सरकार स्थानीय निकायों को अधिकार, संसाधन और जवाबदेही के तीनों स्तंभ मजबूत कर दे, तो शहरों की अनेक बुनियादी समस्याओं का समाधान स्थायी रूप से किया जा सकता है। अब समय केवल शहरों को फैलाने का नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर तरीके से संचालित करने का है।

हमारे शहरों की एक बड़ी समस्या विभागों के बीच समन्वय की कमी है। एक एजेंसी सड़क बनाती है, कुछ समय बाद सीवर या पानी की पाइपलाइन के लिए सड़क खोद दी जाती है। फिर किसी अन्य एजेंसी द्वारा केबल या पाइपलाइन डालने के लिए वही सड़क दोबारा खोदी जाती है।

अदालती चेतावनी को भी कर रहे नजरअंदाज



अनदेखी

रवि शंकर

स्वतंत्र पत्रकार

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक बहुमंजिला इमारत गिरने की घटना में एक बार फिर साबित कर दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में लापरवाही की कीमत लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। जहां कभी अवैध इमारत ढह जाती है, कभी होटलों में आग लग जाती है, कभी पानी कोचिंग सेंटर्स के भीतर घुस जाता है, तो कभी भगदड़ जैसी घटनाएं हो जाती हैं। हर बार जवाबदेही बयानों और कागजों में दबकर रह जाती है। सत्य निकेतन की घटना कोई अकेली त्रासदी नहीं है, बल्कि यह भारत की बढहाल शहरी बुनियादी संरचना और जर्जर इमारतों के उस विशाल संकट का एक खौफनाक प्रतीक है, जहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी, अवैध निर्माण और प्रशासन की घोर लापरवाही इंसानी जिंदगियों पर भारी पड़ रही है।

दिल्ली में इमारत गिरने की यह कोई अकेली घटना नहीं है। बीते दो वर्षों में रोहिणी, साकेत, वेलकम, करोल बाग, पहाड़गांज और मुस्तफाबाद के अलावा दिल्ली के कई अन्य इलाकों में इमारत गिरने की घटनाएं हुईं। दिल्ली की एक बड़ी समस्या अनऑथराइज्ड कॉलोनियां भी हैं, जिसकी वजह से आए दिन कोई न कोई हादसा सुनने में आता ही है। इन इलाकों में लंबे समय से मालिकाना हक, सड़क, सीवर और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की समस्या रही है। अप्रैल 2026 में सरकार ने 1,511 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को 'जैसी है, जहां है' के आधार पर नियमित करने का फैसला किया। दिल्ली में समस्या यह नहीं है कि हर घर असुरक्षित है या हर सड़क जानलेवा है। समस्या यह है कि बार-बार होने वाले हादसे व्यवस्था की कमजोरियां सामने ला रहे हैं। एनसीआरबी की एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया (एडीएसआई) रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 से 2024 के बीच देशभर में कुल 7,874 लोगों की जान चली गई। इसमें सबसे चिंताजनक स्थिति देश की राजधानी में इस तरह की घटनाओं में मौत के आंकड़ों का बढ़ना



भारतीय शहरों की घनी आबादी और जमीनों की ऊंची कीमत भी निम्न मध्यम वर्गीय लोगों को, जिन्होंने किसी तरह से खुद के लिए छोटे मकान का बंदोबस्त किया है, वे ही अतिरिक्त निर्माण के लिए बाध्य हैं। ऐसे सभी निर्माण, योजना कानूनों को धराशायी कर देते हैं। उन्हें स्थानीय निकायों के तर्फ से नोटिस भी दिया जाता है, परंतु आमतौर पर ऐसे हालातों में स्थानीय प्रबंधन का सहारा ले लिया जाता है, ताकि इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए। कई धनाढ्य लोगों के लिए, कानून के कोई

क्या इससे जवाबदेही तय होगी? कामकाज में कोई सुधार आएगा? क्या इस कार्रवाई के बाद इमारतें नहीं ढहेंगी? यह सिर्फ दिल्ली का नहीं, पूरे देश का मामला है। सरकारें क्या कर रही हैं? अधिकारी कब जागेंगे? आम आदमी की जान की कद्र कब होगी? दुर्भाग्यवश, हमें इमानदारीपूर्वक ये मानना होगा कि शहरों में अवैध निर्माण के प्रसार पर समूची रोकथाम नहीं लगाई जा सकी है। इसके सतत बढ़त के पीछे कई वजह हैं। जैसे-जैसे हम बढ़ते हैं और घेरा बनाते जाते हैं, ये शहर अपने साथ-साथ समस्याओं में और भी जटिलताएं लाते हैं।



बुनियादी जरूरत

सुरशील देव

स्वतंत्र पत्रकार

इस समय दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा है, जिसमें चीन,रुस जैसी महाशक्तियां समेत कुल 21 देशों के प्रमुख एक ही भवन पर दिखाई दे रहे हैं। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। यानी दुनिया की नजरें इस समय दिल्ली पर टिकी हैं। सम्मेलन में वैश्विक साझेदार, खुले व्यापार या बदलते शक्ति संतुलन की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस राजधानी में नागरिक सुविधाओं को लेकर भी चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आखिर क्यों किसी खास मौके पर ही सरकारी तंत्र सक्रिय हो जाते हैं और यातायात, सफाई व्यवस्था, सुरक्षा तथा पुलिसिंग सभ ठीक-ठाक हो जाती है? दिल्ली के नागरिकों की ओर से सरकार के समक्ष यह एक बड़ा सवाल है। कहते हैं कि सभी सुविधाओं के लिए सरकार राजधानी शहर में भी सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों से सम्झौता करती है। सरकार कई मोर्चे पर असफल साबित होती हैं। यातायात, सफाई और सुरक्षा व्यवस्था के अलावा कई बुनियादी जरूरतें हैं जिनमें दिलाई, भ्रष्टाचार या लापरवाही शामिल हैं। इनके कारण दिल्ली शहर की लगातार बदनामी होती है।

दिल्ली में सत्य निकेतन की घटना में 9 लोगों की जान चली गई। इनमें ज्यादातर छात्र थे। पांच मंजिला इमारत में नियम-कानून को ताक पर रखकर पीजी चलाया जा रहा था। हालांकि इस घटना में एमसीडी के कई अफसरों को निलंबित कर दिया गया। मकान मालिक को गिरफ्तार किया गया। लेकिन यह सब तब हुआ, जब हादसा हो गई। ऐसे में यह सवाल उठता है कि हादसा होने से पहले प्रशासन नींद से क्यों नहीं जागता? घटना के बाद पड़ताल की जा रही है तो एक के बाद एक ऐसी जर्जर इमारतों का पता चल रहा है, जो बहुत ही खतरनाक हैं। पता नहीं, वह किस दिन गिर जाए और कई जिंदगियां दफन हो जाएं। इन इमारतों में रहने वाले छात्र, जो देश का भविष्य हैं। उनका जीवन हर पल खतरे के साप में रहता है।



गली-मोहल्लों में अवैध निर्माण कर हॉस्टल बना दिए गए हैं। वहां कोई नियम या सरकार की नीति नहीं है। बेहतर प्रबंधन नहीं। जिम्मेदार महकमों से सौदेबाजी कर जहां-तहां बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी जाती है। इनमें होटल और रेस्टोरेंट भी बिना मानक के चला दिए जाते हैं, जो सरासर गलत है।

संचालक उन्हें मौत का दरवाजा तक दिखा देते हैं। उनकी सुविधाओं का जरा भी ख्याल नहीं रखा जाता। किराया वसूली के लिए काम चलाऊ निर्माण जरूर कर दिया जाता है। सभी जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैम्पस के निकट छात्र आवास का सघन बाजार है। निजी पेइंग गेस्ट भी बहुत ज्यादा हैं।

गली-मोहल्लों में अवैध निर्माण कर हॉस्टल बना दिए गए हैं। वहां कोई नियम या सरकार की नीति नहीं है। बेहतर प्रबंधन नहीं। जिम्मेदार महकमों से सौदेबाजी कर जहां-तहां बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी जाती है। इनमें होटल और

कार्यालय ने इस घटना का तुरंत संज्ञान लिया था, लेकिन उस प्रशासनिक छांव का क्या होगा, जो राजधानी शहर में अच्छा होने का दंभ भरते हैं? आखिर, कब तक जर्जर दीवारों के बीच छात्रों का दम घुटना रहेगा? नॉर्थ कैम्पस परिया, लक्ष्मी नगर, रमेश पार्क, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, मुखर्जी नगर और मुनिरका जैसे इलाके में भी सत्य निकेतन जैसे हालात हैं जहां पुरानी इमारतें, संकरी गलियां, भीड़ और कमजोर सुरक्षा इंतजाम दिखते हैं। इसलिए सरकार को मास्टर प्लान 2047 से पहले भी दिल्ली में बहुत कुछ करने और बदलने की जरूरत है।

14.84 लाख परिवारों के नल कनेक्शन का इंतजार करने का दावा, 89 फीसदी तक पानी के नमूने पीने योग्य नहीं पाए गए

हरिभूमि ब्यूरो►नई दिल्ली

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे ने गुजरात में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। खड्गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘हर घर जल’ के दावे की हकीकत दूषित पानी और नल कनेक्शन के लिए इंतजार कर रहे परिवारों के आंकड़ों से सामने आ गई है।

खड्गे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि गुजरात में दशकों से भाजपा का शासन है, लेकिन राज्य में पानी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। उन्होंने दावा किया कि नौ में से करीब 10 पानी के नमूने पीने योग्य नहीं पाए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते वर्ष



2004 में 'सुजलाम-सुफलाम' योजना का प्रचार किया गया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद यही दावे 'जल जीवन मिशन' के रूप में आगे बढ़े। अब

सीएजी की रिपोर्ट ने गुजरात सरकार के वर्ष 2022 में राज्य के सभी ग्रामीण घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने के दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात ने अक्टूबर 2022 तक 91.18 लाख ग्रामीण परिवारों को 100 प्रतिशत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध होने का दावा किया था। हालांकि 27 जिलों की जिला वार्षिक कार्योजनाओं में 1 अप्रैल 2024 तक 14.84 लाख परिवारों के नल कनेक्शन की प्रतीक्षा में होने की बात सामने आई। सीएजी ने इन आंकड़ों के बीच विरोधाभास को देखते हुए आंकड़ों की विश्वसनीयता पर भरोसा जताने में असमर्थता व्यक्त की। ऑडिट में यह भी सामने आया कि सभी 18,024 गांवों को 'हर घर

जल' के अनुरूप बताया गया था, लेकिन अगस्त 2025 तक केवल 16,920 गांवों यानी 93.87 प्रतिशत गांवों को ही इसका प्रमाणन मिला था। छह जिलों में किए गए सर्वेक्षण में नवंबर 2024 तक 71,842 परिवारों यानी करीब 15 प्रतिशत परिवारों के पास कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन नहीं था। पानी की गुणवत्ता पर भी सीएजी ने गंभीर सवाल उठाए। रिपोर्ट की जांच में चुनिंदा गांवों में परीक्षण किए गए पानी के करीब 89 प्रतिशत नमूने पीने योग्य नहीं पाए गए। इसके अलावा 48 गांवों के भौतिक सत्यापन में चार गांवों में पानी की आपूर्ति ही नहीं मिली, जबकि कई अन्य गांवों में निर्धारित 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम पानी की आपूर्ति दर्ज की गई।

रिपोर्ट में जल परियोजनाओं में देरी और

वित्तीय अनियमितताओं का भी उल्लेख है। गुजरात वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 11 बड़ी पाइपलाइन परियोजनाओं में पांच परियोजनाएं आठ से 25 महीने की देरी से पूरी हुईं। ऑडिट में गलत थोक मूल्य सूचकांक के इस्तेमाल से ठेकेदारों को 54.32 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान और गलत जीएसटी दर के कारण 18.65 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान की बात भी सामने आई।

धोलका के पांच गांवों में दूषित पानी को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन भी जारी है। ग्रामीणों का दावा है कि पिछले सात वर्षों में इन गांवों में 54 लोगों की कैंसर से मौत हुई है और रासायनिक प्रदूषण के कारण भूजल प्रभावित हुआ है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

अहमदाबाद के मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है कि इन गांवों में कैंसर के कारणों की जांच की जरूरत है। खड्गे ने सौराष्ट्र के राजकोट और जामनगर सहित कई इलाकों में पेयजल संकट तथा कच्छ-सौराष्ट्र में किसानों के सूखे से जूझने का भी दावा किया। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात की जनता को 2047 के विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा है, जबकि राज्य में लंबे समय से शासन कर रही भाजपा सरकार के दावों और जमीनी स्थिति में अंतर दिखाई दे रहा है। खड्गे ने अपने पोस्ट के अंत में भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि गुजरात में न 'सुजलाम' यानी शुद्ध पानी है और न 'सुफलाम' यानी भरपूर फल एवं उपजाऊ फसलें!

खबर संक्षेप

ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ करने वाला टीटीई अरेस्ट

पलक्कड़। पलक्कड़ के शोरानूर के पास ट्रेन में महिला यात्री से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में टिकट निरीक्षक (टीटीई) को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान कोल्लम के कडक्कल निवासी शिजू के रूप में हुई है। वह रेलवे के तिरुवनंतपुरम मंडल से जुड़ा है।

सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार

कोझिकोड। केरलम के पराम्बा में एक महिला से कथित सामूहिक दुष्कर्म में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

पराम्बा पुलिस थाने ने बताया कि महिला आरोपियों में से एक की रिश्तेदार है। आरोप है कि उसे मादक पदार्थ दिए गए और लॉज तथा घरों समेत अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान दौरा पड़ने से पायलट की मौत

नई दिल्ली। एयर इंडिया के एक पायलट का दिल्ली में प्रशिक्षण के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यह

घटना दिल्ली के एक होटल में हुई, जहां वे लेओवर आराम पर थे। एयर इंडिया ने

कॉकपिट क्रू सदस्य के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। पायलट को शुक्रवार शाम होटल में अचेत पाया गया था।

सोनितपुर में कार-टुक की टक्कर, 5 की मौत

तेजपुर। असम के सोनितपुर जिले में शनिवार को कार और टुक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई।

हादसा रंगापारा थाना क्षेत्र के बालीपारा में एक ट्रेलर पंप के पास चल रहा हुआ जब सामने से आ रहे ट्रक से कार की टक्कर हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसे में मारे गए सभी लोग कार में सवार थे।

कानपुर में 5,600 करोड़ की साइबर लूट का खुलासा

हैदराबाद से गिरोह के 2 शातिर अरेस्ट

आरोपियों की 76 फर्जी कंपनियां मिलीं

एजेंसी►►कानपुर

पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल ठगी का पर्दाफाश किया है। चमनगंज और बेकनगंज के 2 साइबर अपराधियों ने मिलकर पूरे देश में करीब 5,600 करोड़ का फ्रांड किया है।

इन्हें साइबर क्राइम टीम ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है टीम ने रैकेट के सरगना बेकनगंज के तलाक महल निवासी शाहवेज वारिस को हैदराबाद में ट्रेस किया। इन्हें कानपुर लाया गया। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने नेटवर्क का खुलासा किया।

दोनों आरोपी ऑनलाइन गेमिंग, आईपीएल में सट्टा, शेयर मार्केट में निवेश और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। कम समय में पैसा कई गुना करने का झोसा देकर लोगों से उनके बैंक खातों में रकम मंगवाई जाती थी। आरोपियों ने 76 फर्जी कंपनियां बना रखी थीं। इनसे पैसों को ठिकाने लगाते थे। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दोनों के खिलाफ 86 शिकायतें दर्ज हैं। शाहवेज वारिस के 11 बैंक खातों में 170 करोड़ की ठगी की शिकायतें हैं, जबकि सलमान के 2 खातों पर 16 करोड़ से ज्यादा के फ्रांड की 32 शिकायतें हैं।

गुजरात में ‘हर घर जल’ के दावे पर सीएजी की रिपोर्ट से घिरी भाजपा सरकार, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने साधा इस पर निशाना

नड्डा और नायडू ने आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का किया उद्घाटन

स्वास्थ्य प्रणालियों के बुनियादी ढांचे को मिलेगी मजबूती और लोगों को मिलेगा ज्यादा फायदा

एजेंसी►►विजयवाड़ा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.चंद्रबाबू नायडू ने राज्यभर में 249 करोड़ की लागत से स्थापित 10 गहन चिकित्सा खंडों और 12 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) का शनिवार को उद्घाटन किया। गहन चिकित्सा खंडों में कुल 500 बिस्तर हैं और इनमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर के साथ-साथ अल्ट्रासाउंड, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और न्यूरोसर्जरी की सुविधाएं भी मौजूद हैं। उद्घाटन के बाद विजयवाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि यह स्वास्थ्य प्रणालियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। हमने 12 जगहों पर आईपीएचएल और 10 स्थानों पर गहन चिकित्सा खंड का उद्घाटन किया है। नड्डा ने 2020 में आई कोविड-19 महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य प्रणाली और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत को समझा।

‘संजीवनी परियोजना’ राज्य में शुरू होगी: नायडू

नायडू ने कहा कि राजग सरकार हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सुधार किए हैं और कई देशों को कोविड- के टीके उपलब्ध कराए हैं। देश में मेडिकल सीट की संख्या 51 हजार से अधिक बढ़कर दोगुनी से ज्यादा हो गई है और मॉडलिंगरि में एम्स को बेहतर तरीके से विकसित किया जा रहा है। नायडू ने कहा कि स्वास्थ्य रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से जुड़ी ‘संजीवनी

परियोजना’ जल्द पूरे राज्य में शुरू की जाएगी और यह एक बड़ा बदलाव लाएगी। इससे पहले नड्डा और नायडू ने विजयवाड़ा के पुराने सरकारी अस्पताल में एक गहन चिकित्सा खंड और आईपीएचएल का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। बाद में दोनों नेताओं ने इन नई सुविधाओं का दौरा किया जहां अधिकारियों ने उन्हें इनकी विशेषताओं की जानकारी दी।

विजयवाड़ा में 10 गहन चिकित्सा खंडों, 12 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब का लोकार्पण किया



आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए 1,271 करोड़ दिए

उन्होंने कहा कि 2021 में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसरंचना मिशन शुरू किया गया। सरकार ने अगले 5 वर्षों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए 64,180 करोड़ खर्च करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महामारी और आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को तैयार करना है। नड्डा ने कहा कि 23 गहन चिकित्सा खंड, 26 आईपीएचएल और 45 आयुष्मान आरोग्य शहरी मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए 1,271 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई है।

गहन चिकित्सा खंड में सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी

उन्होंने कहा कि गहन चिकित्सा खंड में आपातकालीन सेवाएं, आईसीयू, मृथक वार्ड, बड़े और छोटे ऑपरेशन थिएटर तथा बच्चों के इलाज की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अमरावती वॉलंट बायो वैली को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाते के नायडू के अनुरोध पर नड्डा ने केंद्र के सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक तकनीकी दल राज्य की नई राजधानी में भेजा जाएगा।

मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर

देशभर में एमबीबीएस की 13,186 सीटें बढ़ीं, कुल संख्या 1.40 लाख के पार

मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इस बीच राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने संशोधित सीट मेट्रिक्स जारी कर दी है। अब देश में एम्स जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को छोड़कर एमबीबीएस की 1,40,214 सीटें हो गई हैं। इनमें 61,185 सरकारी सीटों में 2,786 की वृद्धि हुई है। निजी मेडिकल कॉलेजों की 65,843 सीटों में 10,400 सीटें बढ़ी हैं।

कर्नाटक में सर्वाधिक 1,650 वृद्धि उसके बाद तमिलनाडु में

देश में सबसे ज्यादा एमबीबीएस सीटें कर्नाटक में बढ़ाई गई हैं। यहां 1,650 नई सीटें जोड़ी गई हैं। तमिलनाडु में 1,250 और बिहार में 1,240 सीटें बढ़ी हैं। कर्नाटक में एमबीबीएस की कुल 15,745 सीटें हो गई हैं। तमिलनाडु में 14,299 हो गई है।

राजस्थान और तेलंगाना में भी 1,000 से ज्यादा सीटें बढ़ीं

राजस्थान में एमबीबीएस की 1,100 नई सीटें जोड़ी गई हैं। यहां 8,280 सीटें हो गई हैं। तेलंगाना में 1,010 सीटें बढ़ी हैं। बंगाल में 975, छग में 645, महाराष्ट्र में 550 और आंध्र में 525 सीटें हैं।

झारखंड और मध्य प्रदेश में 520-520 सीटें बढ़ीं

झारखंड और मध्य प्रदेश में 520-520 सीटें बढ़ाई गई हैं। हरियाणा में 350, केरल में 300 और गुजरात में 250 सीटों का इजाफा हुआ है।

पूर्व सीएम रावत का कांग्रेस से इस्तीफा पार्टी के संघर्ष में मेरी वजह से कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए

एजेंसी►►देहरादून

उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि उनसे जुड़ी किसी भी चीज की से विधानसभा चुनावों से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी की लड़ाई कमजोर पड़े। रावत ने उन रिपोर्टों का जिक्र किया जिनमें कहा गया था कि उनके पूर्व ओएसडी और सहयोगी जीना के पास से भारी मात्रा में कैश और गहन जब्त किए गए हैं। रावत ने उन्हें सज्जन और मेहनती व्यक्ति बताया और कहा कि सच्चाई सामने आएगी।

उनके पूर्व ओएसडी और सहयोगी जीना के पास से भारी मात्रा में कैश और गहन जब्त किए गए हैं। रावत ने उन्हें सज्जन और मेहनती व्यक्ति बताया और कहा कि सच्चाई सामने आएगी।

मुझे आरोप पर विश्वास नहीं

रावत ने कहा कि अगर रावत ने कहा कि अगर ग्राम सेवकों की भर्ती में ओएमआर शांति के साथ छेड़छाड़ की और कोई भी गलती उन्होंने की है, उसके प्रमाण हैं तो उनके इस तथ्यांकित दुस्साहसिक कृत्य के लिए मैं लज्जित हूं। परंतु मुझे इस आरोप पर विश्वास नहीं हो रहा है।

मुख्यमंत्री सैनी ने दी मंजूरी, फाइनेंशियल मॉडल फॉर स्टेट कंट्रीब्यूशन को लेकर हुई बैठक

कुरुक्षेत्र, नारनौल, जींद तथा सोहना पलवल में

बाड़पास निर्माण कार्य को मिली मंजूरी परियोजनाओं

पर खर्च होंगे 9700 करोड़ रुपए

हरिभूमि ब्यूरो►►नई दिल्ली

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आमजन के लिए बेहतर आवागमन सुनिश्चित करने के लिए एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों एवं कस्बों के बाहर रिंग रोड एवं नेशनल हाईवे बनाने के कार्य को मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सचिवालय में राष्ट्रीय राजमार्गों से शहरी क्षेत्र में भीड़भाड़ कम करने के लिए मास्टर प्लान के तहत एडोशन ऑफ फाइनेंशियल मॉडल फॉर स्टेट



लागत शेयर के लिए वित्त विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों की तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री सैनी ने बैठक में हिसार बाड़पास, कुरुक्षेत्र बाड़पास, नारनौल सिटी बाड़पास, जीन्द बाड़पास तथा सोहना पलवल बाड़पास निर्माण कार्य को स्वीकृति

निर्माण किया जाएगा। लगभग 11 किलोमीटर लम्बे इस बाड़पास को स्टेट हाईवे एनएच 148वीं से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जींद के दूसरी तरफ बाढ़ा रिंग रोड एवं बाड़पास एनएच 352 चार मार्गीय सड़क का निर्माण किया जाएगा। एनएच 919 से पलवल सोहना बाड़पास को भी जीर्णोद्धार एवं रि-डिजाइन कर निर्माण किया जाएगा। यह चार मार्गीय सड़क मार्ग लगभग 24 किलोमीटर लंबाई का होगा। इन परियोजनाओं पर लगभग 9700 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

प्रदान की। हिसार बाड़पास, हिसार-राजगढ़ रोड एनएच 52 से हिसार देहली रोड तथा हिसार कैथल रोड से जोड़ने का कार्य करेगा। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र लाडवा बाड़पास की भी डीपीआर तैयार कर ली गई है। जल्द ही इस परियोजना पर भी कार्य आरम्भ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नारनौल सिटी बाड़पास का भी

कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएनडी-फरीदाबाद-बल्लभगढ़ बाड़पास केएमपी लिंक से देहली मुंबई एक्सप्रेस वे डीएनएल कनेक्टिविटी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए भी तैयार किया जाएगा। कर्नाल रिंग रोड के लिए भी भूमि शेयर जमा करवा दिया गया है। आंबाला शहर एवं कैट से जोड़ने के लिए रिंग रोड का कार्य भी निर्माणाधीन है। बैठक में रेवाड़ी मॉडिडा रेलवे लाइन पर सिरसा में स्थित स्टेशन रोड पर रेलवे अंडर बिज निर्माण तथा कजीना महेंद्रगढ़ रोड से अनाववास, दाणी राजावास स्कूल से बलाना, खातोद से बुडीन, किम्मेड़ा और बलैवा के लिए लिंक रोड, महेंद्रगढ़ बुचौली रोड, नांगवास से अटेली सड़क के अतिरिक्त कार्य को भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह, अनुग्राह अखावाल, आयुक्त एवं सचिव अश्लमा बराड़ जे गणेशन भी मौजूद रहे।

केंद्रीय मंत्री ने राज्यों, सरकारी विभागों और निजी क्षेत्र में स्वदेशी स्टील स्लैंग रोड तकनीक को बढ़ावा देने का आह्वान किया

IESS WORLD RECORD CERTIFICATION CEREMONY



स्टील स्लैंग की सड़कें निर्माण लागत में कर सकती हैं 40 प्रतिशत तक की कटौती: जितेंद्र सिंह

हरिभूमि ब्यूरो►►नई दिल्ली

स्टील स्लैंग रोड टेक्नोलॉजी सड़क निर्माण लागत को लगभग 40 प्रतिशत तक कम कर सकती है, जबकि पारंपरिक सड़कों की तुलना में चार गुना अधिक मजबूती प्रदान करती है। यह बात शनिवार को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि यह तकनीक सड़कों के रखरखाव चक्र को भी काफी बढ़ा सकती है—इसमें लगभग 15 वर्षों के बाद ही रखरखाव की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसी क्रांतिकारी ब्रेकथ्रू है जिसके प्रभाव न केवल सड़क इंजीनियरिंग पर, बल्कि संपूर्ण बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस स्वदेशी तकनीक को एक परियोजना से कई परियोजनाओं तक और एक राज्य से कई राज्यों तक ले जाने का आह्वान किया। उन्होंने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ-साथ रेलवे, अन्य सरकारी विभागों, राज्य सरकारों, निजी बिल्डरों, ठेकेदारों और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर्स द्वारा भी इसे व्यापक रूप से अपनाए जाने पर बल दिया। डॉ. जितेंद्र सिंह सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीआरआरआई) नई दिल्ली और जंदल स्टील लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से हासिल किए गए 'प्रसंस्कृत स्टील स्लैंग एग्जीगेट्स से बनी विश्व की सबसे लंबी सड़क' के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दुनिया की सबसे लंबी स्टील स्लैंग सड़क के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया

प्रदान किये जाने वाले समारोह में बोल रहे थे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बनी 1.85 किलोमीटर लंबी यह सड़क स्वदेशी तकनीक के बड़े पैमाने पर विस्तार को दर्शाती है, जो इस्पात उत्पादन के उप-उत्पाद (प्रसंस्कृत स्टील स्लैंग) को सड़क निर्माण के लिए एग्जीगेट्स में परिवर्तित करती है। इस कार्यक्रम के दौरान सड़क का वर्चुअल उद्घाटन, एक साइटिफिक डॉक्यूमेंट्री का विमोचन, सीएसआईआर-सीआरआरआई और जंदल स्टील के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर, 'स्टील गिट' ब्रांड का शुभारंभ और प्रोजेक्ट टीम का सम्मान भी संपन्न हुआ। इस अवसर पर संसद सदस्य एवं जंदल स्टील के अध्यक्ष तथा इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन जंदल, डीएसआईआर की सचिव एवं सीएसआईआर की महानिदेशक डॉ. एन. कलाईसेल्वी, नीति आयोग के पूर्व सदस्य एवं डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक डॉ. वी.के. सारस्वत, सीएसआईआर-सीआरआरआई के निदेशक डॉ. सी.एच. रवि शेखर, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, इंजीनियर, इंडस्ट्री लीडर्स और मीडियाकर्ता उपस्थित थे।

कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएनडी-फरीदाबाद-बल्लभगढ़ बाड़पास केएमपी लिंक से देहली मुंबई एक्सप्रेस वे डीएनएल कनेक्टिविटी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए भी तैयार किया जाएगा। कर्नाल रिंग रोड के लिए भी भूमि शेयर जमा करवा दिया गया है। आंबाला शहर एवं कैट से जोड़ने के लिए रिंग रोड का कार्य भी निर्माणाधीन है। बैठक में रेवाड़ी मॉडिडा रेलवे लाइन पर सिरसा में स्थित स्टेशन रोड पर रेलवे अंडर बिज निर्माण तथा कजीना महेंद्रगढ़ रोड से अनाववास, दाणी राजावास स्कूल से बलाना, खातोद से बुडीन, किम्मेड़ा और बलैवा के लिए लिंक रोड, महेंद्रगढ़ बुचौली रोड, नांगवास से अटेली सड़क के अतिरिक्त कार्य को भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह, अनुग्राह अखावाल, आयुक्त एवं सचिव अश्लमा बराड़ जे गणेशन भी मौजूद रहे।

आर्थिक आजादी की असली सुरक्षा कमाई के साथ जोखिम का भी बीमा

- बाढ़, आग, सड़क हादसे व साइबर ठगी जैसे जोखिम एक झटके में खत्म की रहे जमा पूंजी
- अब निवेश के साथ बीमा सुरक्षा को भी वित्तीय योजना का जरूरी हिस्सा बनाने की जरूरत

सुरक्षा बिजनेस डेस्क

आर्थिक आजादी का मतलब सिर्फ अच्छी कमाई, बैंक में पर्याप्त पैसा या शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश होना नहीं है। असली आर्थिक मजबूती तब मानी जाती है, जब अचानक आने वाला बड़ा खर्च भी परिवार की वर्षों की बचत और निवेश को हिला न सके। बीमारी, सड़क हादसा, घर या दुकान में आग, प्राकृतिक आपदा और अब साइबर ठगी जैसे जोखिम कभी भी सामने आ सकते हैं। ऐसे में बीमा केवल किसी नुकसान की भरपाई का साधन नहीं, बल्कि पूरी वित्तीय योजना को सुरक्षित रखने वाली ढाल बन जाता है। अक्सर निवेशक अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन उस संपत्ति को जोखिम से बचाने की योजना पीछे छूट जाती है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने कई वर्षों में बचत करके घर बनाया, बच्चों की पढ़ाई के लिए निवेश किया और सेवानिवृत्ति के लिए अलग कोष तैयार किया। यदि अचानक कोई बड़ा हादसा हो जाए और लाखों रुपये का खर्च सामने आ जाए तो वह व्यक्ति अपने निवेश को समय से पहले निकालने के लिए मजबूर हो सकता है। बाजार में गिरावट के समय निवेश बेचने की स्थिति पैदा हो जाए तो आर्थिक नुकसान और बढ़ सकता है।



बीमा और निवेश की भूमिका अलग-अलग

वित्तीय योजना में बीमा और निवेश को एक-दूसरे का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। निवेश का मुख्य उद्देश्य समय के साथ धन बढ़ाना है, जबकि बीमा का उद्देश्य बड़े जोखिम से आर्थिक सुरक्षा देना है। इसलिए पहले पर्याप्त बीमा सुरक्षा तैयार करना और उसके बाद लक्ष्य से आर्थिक सुरक्षा देना है। जीवन बीमा परिवार के कमाने वाले सदस्य की अनुपस्थिति में आर्थिक सुरक्षा देता है। स्वास्थ्य बीमा अचानक आने वाले अस्पताल खर्च से बचाने में मदद करता है। वाहन बीमा सड़क दुर्घटना से जुड़े नुकसान को संभालने में उपयोगी है। घर और कारोबार के लिए संपत्ति बीमा आग, प्राकृतिक आपदा या अन्य निधारित जोखिमों में वित्तीय सुरक्षा दे सकता है। छोटे कारोबारियों के लिए यह सुरक्षा

और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। दुकान, मशीनरी, माल और कारोबार से जुड़े जोखिमों के लिए उचित बीमा न होने पर एक दुर्घटना का असर केवल मालिक की संपत्ति पर नहीं, बल्कि पूरे कारोबार और कर्मचारियों की आय पर पड़ सकता है।

साइबर ठगी बना नया आर्थिक जोखिम

डिजिटल लेनदेन बढ़ने के साथ वित्तीय जोखिमों का स्वरूप भी बदल रहा है। पहले चोरी, आग या प्राकृतिक आपदा जैसे जोखिम प्रमुख माने जाते थे, अब साइबर ठगी भी आम व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा के सामने बड़ी चुनौती है। फर्जी बैंक कॉल, गलत लिंक, पंहुचान संबंधी जानकारी की चोरी और दूसरे डिजिटल धोखे से लोग अपनी जमा पूंजी गंवा सकते हैं। हालांकि हर तरह का साइबर नुकसान सामान्य बीमा से स्वतः सुरक्षित नहीं होता। इसलिए किसी भी साइबर सुरक्षा उत्पाद या बीमा योजना को लेने

वित्तीय योजना में सुरक्षा की चार परतें

एक मजबूत वित्तीय योजना को चार स्तरों में देखा जा सकता है। पहला, रोजमर्रा और अचानक आने वाले छोटे खर्चों के लिए आपातकालीन निधि। दूसरा, परिवार के लिए पर्याप्त जीवन बीमा। तीसरा, स्वास्थ्य और दूसरी जरूरी बीमा सुरक्षा। चौथा, लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए विविध निवेश। इन चारों को अलग-अलग उद्देश्य के साथ तैयार करने से किसी एक संकट का असर पूरी आर्थिक योजना पर नहीं पड़ता। इसके साथ ही नामांकित व्यक्ति की जानकारी, पॉलिसी दस्तावेज और दावा प्रक्रिया से जुड़े जरूरी कागजात परिवार के सदस्यों को भी पता होने चाहिए।

पॉलिसी लेते समय जल्दबाजी से बचें

बीमा खरीदते समय केवल प्रीमियम की राशि देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। बीमित राशि, जोखिम का दायरा, दावा निपटाने की प्रक्रिया, प्रतीक्षा अवधि, अपवर्जन और नवीनीकरण की शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। जीवन और स्वास्थ्य बीमा में अपनी वास्तविक जरूरत के मुताबिक कवरज तय करना चाहिए। संपत्ति या कारोबार का बीमा लेते समय भी यह देखना जरूरी है कि पॉलिसी में वास्तविक संपत्ति और संभावित जोखिम पर्याप्त रूप से शामिल हैं या नहीं। किसी भी पॉलिसी में दावा करने की समयसीमा और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी पहले से रखना बाद में परेशानी कम कर सकता है।

से पहले यह समझना जरूरी है कि उसमें किन परिस्थितियों में दावा स्वीकार किया जाता है और किन परिस्थितियों को बाहर रखा गया है। केवल बीमा खरीद लेना पर्याप्त नहीं है, उसकी शर्तों को समझना भी उतना ही जरूरी है।

कम बीमा, ज्यादा वित्तीय जोखिम

भारत में बड़ी आबादी अभी भी बीमा को निवेश या बचत का साधन मानकर खरीदती है। कई लोग केवल इसलिए पॉलिसी लेते हैं क्योंकि उसमें भविष्य में पैसा मिलने की उम्मीद होती है। इस सोच में जोखिम सुरक्षा का मूल उद्देश्य पीछे छूट सकता है। विशेषज्ञों की नजर में बीमा खरीदते समय पहला सवाल यह होना चाहिए कि परिवार या संपत्ति को वास्तविक रूप से कितनी सुरक्षा चाहिए। उसके बाद प्रीमियम, अवधि, कवरज, अपवर्जन और दावा प्रक्रिया को देखना चाहिए। कम प्रीमियम देखकर ऐसी पॉलिसी चुनना जिसमें वास्तविक जोखिम के समय पर्याप्त

भुगतान न मिले, वित्तीय योजना को कमजोर कर सकता है।

आपदा के समय निवेश बचाने का काम

बीमा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह संकट के समय निवेश को समय से पहले तोड़ने की जरूरत कम कर सकता है। मान लीजिए किसी परिवार के पास बच्चों की शिक्षा और सेवानिवृत्ति के लिए अलग-अलग निवेश हैं। अचानक घर में आग लगने से बड़ा नुकसान हो जाता है। यदि पर्याप्त संपत्ति बीमा है तो नुकसान की भरपाई में बीमा मदद कर सकता है और परिवार को अपने दीर्घकालिक निवेश को तोड़ने से बचाया जा सकता है। इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी बड़े खर्च के समय स्वास्थ्य बीमा परिवार की बचत पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकता है। इसका सीधा लाभ यह है कि निवेश को उसके निर्धारित लक्ष्य तक जारी रखने की संभावना बढ़ती है।

नकद, सोना और एफडी के साथ एसआईपी, म्यूचुअल फंड में लगा रहे पैसा छोटे निवेशकों की बढ़ती भागीदारी से तेज हो रहा वित्तीय बचत का दौर

गुल्लक से बाजार तक पहुंचा पैसा बदल रही बचत की तस्वीर

सुझाव बिजनेस डेस्क

भारतीय परिवारों के लिए पैसा बचाने का मतलब लंबे समय तक घर में नकद रखना, सोना खरीदना, जमीन लेना या बैंक की सावधि जमा में रकम लगाना रहा है। लेकिन अब इस सोच में धीरे-धीरे बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। परिवारों की बचत का एक हिस्सा बैंक और पारंपरिक साधनों से निकलकर म्यूचुअल फंड, एसआईपी और शेयर बाजार जैसे वित्तीय साधनों की ओर बढ़ रहा है। यानी बचत की पुरानी आदत खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसके साथ निवेश की नई आदत तेजी से जुड़ रही है। इस बदलाव का सबसे बड़ा संकेत घरेलू बचत में वित्तीय साधनों की बढ़ती हिस्सेदारी है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 23 में घरेलू बचत में वित्तीय बचत की हिस्सेदारी करीब 27 फीसदी थी, जो वित्त वर्ष 25 में बढ़कर 33 फीसदी हो गई। वहीं, वित्त वर्ष 25 में प्रतिभूति बाजार के माध्यम से परिवारों की बचत का प्रवाह बढ़कर करीब 6.91 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 24 में यह करीब 3.58 लाख करोड़ रुपये था।

एफडी के साथ अब बाजार भी विकल्प

भारतीय परिवारों की वित्तीय मानसिकता में बदलाव का मतलब यह नहीं है कि बैंक जमा या एफडी का महत्व खत्म हो गया है। बैंक जमा आज भी बचत का बड़ा माध्यम है। लेकिन अब निवेशक अपने पूरे पैसे को एक ही जगह रखने के बजाय अलग-अलग साधनों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिस्सा बैंक में तरल जरूरतों के लिए रखा जा रहा है, कुछ पैसा बीमा और सेवानिवृत्ति योजनाओं में जा रहा है और लंबी अवधि के लक्ष्य के लिए म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार का रास्ता अजानाया जा रहा है। हालिया आंकड़ों में भी यही बदलाव दिखाई देता है। वित्त वर्ष 25 में घरेलू वित्तीय परिसंपत्तियों में म्यूचुअल फंड में प्रवाह करीब 4.7 लाख करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 24 के करीब 2.4 लाख करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है।

एसआईपी ने बदली निवेश की आदत

म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ने की एक बड़ी वजह एसआईपी का बढ़ता चलन है। पहले शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए लोगों को बड़ी रकम की जरूरत महसूस होती थी। एसआईपी ने इस धारणा को बदला है। अब नियमित अंतराल पर छोटी रकम निवेश करना संभव है। इससे निवेश बाजार में एकमुश्त पैसा लगाने के बजाय धीरे-धीरे निवेश करने की आदत में बदल रहा है। सरकार के एक हालिया आधिकारिक विवरण के मुताबिक वार्षिक घरेलू वित्तीय बचत में इक्विटी और म्यूचुअल फंड में हिस्सेदारी वित्त वर्ष 12 के करीब 2 फीसदी से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 15.2 फीसदी से ज्यादा हो गई। इसी अवधि में एसआईपी का औसत मासिक प्रवाह भी कई गुना बढ़ा है। यह बदलाव निवेश की



संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि नियमित निवेश बाजार की तेजी या मंदी के बजाय निवेशक की वित्तीय दिनचर्या का हिस्सा बन सकता है।

छोटे शहरों से भी बड़ी भागीदारी

बाजार आधारित निवेश को लंबे समय तक बड़े शहरों और ज्यादा कमाई वाले लोगों के जोड़कर देखा जाता था। डिजिटल प्लेटफॉर्म और आसान ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा ने इस तस्वीर को बदला है। अब निवेश शुरू करने के लिए बड़े शहर में रहना या किसी निवेश कार्यालय तक जाना जरूरी नहीं रह गया। मोबाइल फोन और डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने वित्तीय उत्पादों तक पहुंच आसान की है। इससे छोटे शहरों और कस्बों के निवेशकों की भागीदारी बढ़ने का रास्ता खुला है। युवा निवेशकों के लिए यह बदलाव और ज्यादा स्पष्ट है। वे बचत को केवल भविष्य की जरूरत के लिए सुरक्षित रखने के बजाय उसे लंबी अवधि में बढ़ाने के विकल्प में तलाश रहे हैं।

महिलाओं की भागीदारी अहम

बदलती बचत संस्कृति में महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो रही है। परिवार के वित्तीय फैसलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ निवेश के साधनों की समझ भी बढ़ रही है। महिलाएं अब केवल सोना या बचत खाते तक सीमित नहीं हैं। म्यूचुअल फंड, एसआईपी और दूसरे वित्तीय साधनों को लेकर जानकारी बढ़ रही है। इससे परिवार के निवेश निर्णय पहले की तुलना में ज्यादा विविध हो सकते हैं। हालांकि केवल निवेश खाता खोलना वित्तीय समझदारी की गारंटी नहीं है। बचत का पैसा बाजार तक पहुंचाना निश्चित रूप से वित्तीय क्षेत्र के विस्तार का संकेत है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी बढ़ता है। बैंक जमा और बाजार आधारित निवेश की प्रकृति अलग है। शेयर और इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड में रिस्क निश्चित नहीं होता और बाजार में उतार-चढ़ाव का असर निवेश पर पड़ता है। यही वजह है कि बाजार में निवेश बढ़ने के साथ वित्तीय शिक्षा भी जरूरी हो जाती

है। सिर्फ सोशल मीडिया पर किसी की सलाह देखकर शेयर खरीदना या बाजार तेजी में देखकर निवेश बढ़ाना जोखिमपूर्ण हो सकता है। निवेशकों को अपने लक्ष्य और जोखिम क्षमता के अनुसार निवेश का चुनाव करना चाहिए। छोटी अवधि की जरूरत का पैसा अस्थायिक जोखिम वाले साधनों में लगाने से बचना जरूरी है।

बचत से पोर्टफोलियो तक पहुंच रहा परिवार

भारतीय परिवारों की वित्तीय सोच में सबसे बड़ा बदलाव शायद यही है कि अब बचत को केवल एक जगह जमा करके रखने के बजाय अलग-अलग उद्देश्यों में बांटने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। घर का जरूरी खर्च और आपातकालीन जरूरतों के लिए सुरक्षित रकम, बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग निवेश, सेवानिवृत्ति के लिए लंबी अवधि की योजना और संपत्ति बढ़ाने के लिए बाजार आधारित निवेश-यह सोच धीरे-धीरे जगह बना रही है। यानी परिवार अब केवल लंबे समय तक रहना कि "पैसा कहाँ सुरक्षित रहेगा?", बल्कि यह भी पूछ रहा है कि "पैसा कितने समय में और किस लक्ष्य के लिए बढ़ सकता है?"

आने वाले वर्षों में और बढ़ सकता है वित्तीय निवेश

भारत की युवा आबादी, डिजिटल वित्तीय दांचा और निवेश उत्पादों तक बढ़ती पहुंच इस बदलाव को आगे बढ़ा सकती है। हालिया आंकड़ों में भी वित्तीय परिसंपत्तियों की ओर बढ़ती रुचि साफ दिखाई देती है। हालांकि भारत में परिवारों की बड़ी संपत्ति अभी भी मौक्त परिसंपत्तियों में है।

का बड़ा हिस्सा नए खर्च में चला जाता है। बेहतर कार, महंगा मोबाइल, बड़ा घर, बाहर खाना और बार-बार छुट्टियों पर खर्च जैसी चीजें धीरे-धीरे मासिक बजट का हिस्सा बढ़ा देती हैं। इसे जीवनशैली की महंगवाई कहा जा सकता है। इससे बचने का आसान तरीका यह है कि वेतनवृद्धि का पूरा फायदा खर्च में न लगाया जाए।

चौथी आदत : बीमा को निवेश नहीं, सुरक्षा मानें

वित्तीय योजना में बीमा की भूमिका को लेकर अक्सर भ्रम रहता है। कई लोग बीमा को भी निवेश की तरह देखते हैं और रिटर्न की तुलना करने लगते हैं। जबकि बीमा का मूल उद्देश्य बड़े वित्तीय जोखिम से सुरक्षा देना है। स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति में अस्पताल का बड़ा खर्च वर्षों की बचत पर भारी पड़ सकता है। पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा ऐसी स्थिति में बचत और निवेश को अचानक निकालने की जरूरत कम कर सकता है। इसी तरह परिवार के कमाने वाले सदस्य के साथ अनहोनी होने पर जीवन बीमा परिवार की आर्थिक जरूरतों को संभालने में मदद कर सकता है। इसलिए निवेश की योजना बनाने से पहले जरूरी जोखिमों के लिए पर्याप्त सुरक्षा तैयार करना समझदारी है। बीमा का चुनाव केवल प्रीमियम देखकर नहीं, बल्कि कवरज और शर्तों को समझकर करना चाहिए।



पहली बार निवेश कर रहे हैं तो इन 5 गलतियों से बचें

निवेश गंठा बिजनेस डेस्क

निवेश की दुनिया में पहला कदम रखना जितना उत्साहजनक होता है, उतना ही महत्वपूर्ण यह समझना भी है कि शुरुआत कहाँ से और कैसे की जाए। अक्सर नए निवेशक किसी दोस्त की सलाह, इंटरनेट पर मिली जानकारी या बाजार में चल रही चर्चा के आधार पर पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन निवेश का सही तरीका किसी एक उत्पाद को चुनने से नहीं, बल्कि अपनी जरूरत, लक्ष्य, समय और जोखिम को समझने से शुरू होता है। नए निवेशकों के लिए कुछ बुनियादी नियम ऐसे हैं, जिन्हें शुरुआत में ही समझ लिया जाए तो आगे की कई वित्तीय गलतियों से बचा जा सकता है।

1. बीमा और निवेश को एक ही नजर से न देखें

भारत में कई परिवारों के लिए पहली बड़ी वित्तीय योजना जीवन बीमा होती है। इसलिए लोग बीमा पॉलिसी को निवेश का माध्यम भी मान लेते हैं। लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग है। बीमा का प्राथमिक मकसद परिवार को वित्तीय जोखिम से सुरक्षा देना है, जबकि निवेश का लक्ष्य समय के साथ संपत्ति तैयार करना है। इसलिए जीवन बीमा की जरूरत हो तो अपनी परिस्थितियों के मुताबिक पर्याप्त सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। वहीं धन बनाने के लिए अलग निवेश योजना बनाई जा सकती है। इससे निवेशक को यह समझने में मदद मिलती है कि वह कितना पैसा सुरक्षा के लिए और कितना पैसा संपत्ति बनाने के लिए लगा रहा है।

2. पूरा पैसा एक ही जगह न लगाएं

निवेश में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है विविधता। अपनी पूरी रकम किसी एक ही साधन या संपत्ति वर्ग में लगाने से जोखिम बढ़ सकता है। अलग-अलग परिसंपत्ति वर्गों का दर्शन एक जैसा नहीं होता। बाजार आधारित निवेश में उतार-चढ़ाव हो सकता है, जबकि सुरक्षित माने जाने वाले साधनों में रिटर्न की क्षमता अलग हो सकती है। सोने की कीमत भी अलग परिस्थितियों में बदलती है। इसलिए निवेशक अपनी जोखिम क्षमता और लक्ष्य के आधार पर अलग-अलग साधनों में संतुलन बना सकते हैं। इसका उद्देश्य किसी एक निवेश से सबसे ज्यादा रिटर्न हासिल करना नहीं, बल्कि पूरे निवेश को एक ही जोखिम से बचाना है।

3. सेवानिवृत्ति दूर है तो भी शुरुआत आज से करें

युवा उम्र में सेवानिवृत्ति काफी दूर लगती है। इसी वजह से बहुत से लोग इसे लक्ष्य के लिए निवेश टालते रहते हैं। लेकिन लंबी अवधि के

बीमा को निवेश न समझें और पूरा पैसा एक ही साधन में न लगाएं

शुरुआती निवेशक अक्सर करते हैं कुछ गलतियाँ

सही शुरुआत लंबे समय में बना सकती है मजबूत वित्तीय आधार

निवेश में समय सबसे महत्वपूर्ण साथी बन सकता है। छोटी उम्र में निवेश शुरू करने का फायदा यह है कि छोटी-छोटी नियमित रकम भी लंबे समय में बड़ा कोष तैयार करने में योगदान दे सकती है। इसका कारण चक्रवृद्धि का प्रभाव है, जिसमें निवेश पर मिलने वाला लाभ आगे अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता पैदा करता है। इसलिए सेवानिवृत्ति के लिए निवेश शुरू करने के लिए बड़ी रकम का इंतजार जरूरी नहीं है। आय बढ़ने के साथ निवेश की राशि धीरे-धीरे बढ़ाई जा सकती है।

4. पैसे लगाने से पहले वित्तीय समझ बढ़ाएं

निवेश करना अब पहले की तुलना में आसान हो गया है। मोबाइल फोन से खाता खुल सकता है और कुछ ही मिनेट में निवेश भी शुरू किया जा सकता है। लेकिन निवेश की प्रक्रिया आसान होने का मतलब यह नहीं है कि हर उत्पाद समझना भी आसान है। नए निवेशक को यह समझना चाहिए कि किसी निवेश में पैसा कैसे काम करता है, उसमें कितना जोखिम है, शुल्क कितना है और पैसा कितने समय के लिए लगाया जाना चाहिए। किसी उत्पाद का पिछला प्रदर्शन उसके भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं होता। सोशल मीडिया या परिचितों की सलाह पर बिना समझे पैसा लगाने के बजाय जरूरत पड़ने पर योग्य वित्तीय सलाहकार की मदद लेना बेहतर हो सकता है। जब निवेश की रकम बड़ी हो या लक्ष्य लंबी अवधि का हो।

5. सारी कमाई सिर्फ निवेश में न लगाएं

वित्तीय अनुशासन का अर्थ यह नहीं है कि वर्तमान जिंदगी की हर छोटी खुशी को टाल दिया जाए। निवेश जरूरी है, लेकिन परिवार व जरूरतों के लिए खर्च करना वित्तीय योजना का हिस्सा है। मासिक बजट बनाने समय बचत, निवेश और जरूरतों के साथ मनोरंजन और व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए भी एक उचित रकम जरूरी है। इससे निवेश योजना बोझ जैसी महसूस नहीं होती और लंबे समय तक जारी रखना आसान रहता है। अगर लगातार अपनी जरूरतों और इच्छाओं को दबाता रहे तो वित्तीय योजना लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रह सकती।

शुरुआत छोटी हो सकती है, योजना बड़ी रखें

पहली बार निवेश करने वाले व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वह किसी एक निवेश के पीछे भागने के बजाय अपनी पनी वित्तीय तस्वीर को समझे। पहले जरूरी खर्चों और आपातकालीन जरूरतों के लिए व्यवस्था करें, फिर बीमा सुरक्षा सुनिश्चित करें और उसके बाद लक्ष्य के अनुसार निवेश की योजना बनाएं। निवेश का चुनाव उम्र, आय, लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार बदल सकता है।



कमाई बढ़ने के साथ खर्च बढ़ा तो हाथ रह सकता है खाली बचत को प्राथमिकता, नियमित निवेश, जीवनशैली पर नियंत्रण जरूरी सालाना वित्तीय समीक्षा लंबे समय में बना सकती है मजबूत संपत्ति

सैलरी बढ़ने से नहीं, पैसे की सही चाल से बनती है दौलत

जानकारी बिजनेस डेस्क

अच्छी नौकरी, बढ़ती सैलरी और हर साल मिलने वाली वेतनवृद्धि किसी भी व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत होने का भरोसा देती है, लेकिन ज्यादा कमाई अपने आप में दौलत की गारंटी नहीं है। कई बार आय बढ़ने के साथ खर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ जाता है और महीने के अंत में बचत पहले जितनी ही रह जाती है। इसके उलट आय वाला व्यक्ति अगर खर्च पर नियंत्रण रखे, नियमित बचत करे और लंबे समय तक अनुशासन के साथ निवेश करता रहे तो वह अच्छी संपत्ति बना सकता है। यही वजह है कि धन बनाने की प्रक्रिया में कमाई के साथ पैसे को संभालने की आदतों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। वित्तीय विशेषज्ञों के मुताबिक आर्थिक मजबूती किसी एक बड़े निवेश या अचानक मिले बड़े रिटर्न से नहीं बनती। यह छोटे-छोटे लेकिन लगातार लिए गए सही वित्तीय फैसलों का परिणाम होती है।



पहली आदत : बचत बाद में नहीं, पहले

ज्यादातर लोगों की आर्थिक दिनचर्या कुछ ऐसी होती है कि पहले घर का खर्च, बिल, खरीदारी और दूसरी जरूरतें पूरी की जाती हैं और महीने के अंत में बची रकम को बचत में डालने की कोशिश होती है। समस्या यह है कि अक्सर महीने के अंत तक बचाने के लिए कुछ खास बचता ही नहीं इसके बजाय वेतन आते ही बचत की अक्सर महीने की रकम अलग कर देना ज्यादा प्रभावी तरीका हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की मासिक आय एक लाख रुपये है तो वह अपनी क्षमता के मुताबिक 20 से 30 हजार रुपये पहले ही बचत या नियमित निवेश के लिए अलग कर सकता है। इसके बाद बची रकम में महीने का खर्च चलाने की

आदत बनाई जा सकती है। इसका फायदा यह है कि बचत इच्छा पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि वित्तीय दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है।

दूसरी आदत: बाजार के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं

निवेश शुरू करना आसान है, लेकिन बाजार में गिरावट आने पर निवेश जारी रखना ज्यादा मुश्किल होता है। शेयर बाजार में तेजी के दौरान निवेशक उत्साहित होते हैं और गिरावट में कई लोग डरकर निवेश रोक देते हैं या जल्दबाजी में अपनी हिस्सेदारी बेच देते हैं। लंबी अवधि के निवेश में सबसे महत्वपूर्ण चीज नियमितता और अनुशासन है। निवेश का तरीका व्यक्ति की आय, जोखिम उठाने की क्षमता और वित्तीय लक्ष्य के अनुसार होना चाहिए। भविष्य के लक्ष्य के लिए अलग-अलग साधनों में निवेश का संतुलन बनाया जा सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि, सार्वजनिक भविष्य निधि, पेंशन योजनाएं, म्यूचुअल फंड और अन्य साधनों की भूमिका व्यक्ति की जरूरत के अनुसार अलग हो सकती है।

तीसरी आदत : आय बढ़े तो पूरा खर्च न बढ़ाएं

सैलरी बढ़ने के साथ जीवनशैली में बदलाव स्वाभाविक है। समस्या तब शुरू होती है जब आय में हुई हर वृद्धि

पांचवीं आदत : साल में एक बार पूरे पैसे का हिसाब

निवेश शुरू करने के बाद उसे मूल जाना भी सही रणनीति नहीं है। आय, खर्च, कर्ज, बीमा और निवेश की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। इसलिए साल में कम से कम एक बार पूरी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। इस समीक्षा में देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष कितना पैसा बचा, निवेश कितना बढ़ा, कर्ज कितना कम हुआ और क्या मौजूदा निवेश अभी भी तय लक्ष्य के मुताबिक है। आय बढ़ने पर निवेश की रकम बढ़ाई जा सकती है।

दौलत बनाने का असली सूत्र

धन निर्माण को एक सरल क्रम में समझा जा सकता है। कमाई बढ़ाएं, बचत पहले करें, जोखिम से सुरक्षा लें, नियमित निवेश करें और समय-समय पर समीक्षा करते रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निवेश के लिए छोटी रकम से शुरुआत करके समय के साथ निवेश बढ़ाना अधिक व्यावहारिक हो सकता है। नियमित निवेश लंबे समय में चक्रवृद्धि का फायदा मिलने की संभावना बढ़ती है। अमीर बनने का फार्मूला या रातोरात पैसा देगुना करने वाली योजना नहीं है। मजबूत संपत्ति आमतौर पर लगातार किए गए छोटे वित्तीय फैसलों से बनती है।

सूर्यवंशी या सैमसन?

अफगानिस्तान के खिलाफ चयन की दुविधा

एजेसी ►► नई दिल्ली

अफगानिस्तान के खिलाफ रविवार को 3 मैचों की टी20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत के सामने दुविधा होगी कि 'बंडर ब्वाय' वैभव सूर्यवंशी को उतारा जाए या संजू सैमसन के अनुभव पर भरोसा किया जाए।

■ आज टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20	सूर्यवंशी को इंग्लैंड में सैमसन की जगह अंतिम एकादश में जगह दी गई थी लेकिन श्रृंखला के आखिरी मैच में
---	---

15 वर्ष के सूर्यवंशी की जगह सैमसन को उतारा गया। टी20 प्रारूप में सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी कामयाब रही है। उम्मीद है कि कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर जापान में होने वाले एशियाई खेलों की अंतिम एकादश तय करने से पहले सैमसन और सूर्यवंशी दोनों को बराबर मौके देंगे।

अव्यास सत्र में सैमसन अधिक संतुलित

अभ्यास सत्र के दौरान सूर्यवंशी की तुलना में सैमसन अधिक संतुलित नजर आए। सूर्यवंशी को जसप्रीत बुमराह की गेंदों पर सहज होकर खेलने में समय लगा क्योंकि पिच से भी बुमराह की गेंदों को मदद मिल रही थी। यह भी हो सकता है कि लगातार लाल गेंद के तीन मैच खेलने के बाद सूर्यवंशी को सामंजस्य बिठाने में समय लग रहा हो। वैसे अफगानिस्तान के पास बुमराह जैसा कोई गेंदबाज नहीं है। अफगानिस्तान के गेंदबाजों के सामने सूर्यवंशी को फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं करने पर भी दिक्कत नहीं आएगी।



सूर्यवंशी को लेकर हाइप बढ़ी	टीमें इस प्रकार
सैमसन की बात करें तो तीन पारियों में नाकामी के बाद उन्हें इंग्लैंड दौरे से बाहर करना ज्यादा ही था। लेकिन सूर्यवंशी को लेकर हाइप इतनी बढ़ गई थी कि टीम प्रबंधन ने जनता की मांग पर फैसला लिया भले ही बार-बार वे कहते हों कि बाहरी आवाज का असर नहीं होता। अगर इशान किशन नहीं खेल पाते हैं तो सूर्यवंशी और सैमसन दोनों को मौका मिल सकता है। इशान को नेट अव्यास के दौरान कमर में चोट लगी थी।	भारत : श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, लिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अश्वीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई अफगानिस्तान : इब्राहिम जदरान (कप्तान), दारविश रसूल, नूर उल रहमान, रहमानुल्लाह गुरबाज, सैदिकुल्लाह अटल, अजमलुल्लाह उमरजद, राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुलबर्दिन नायब, नांगेलिया खरोटे, अब्दुल्लाह अहमदजद, फजलहक फारूकी, नवीजुल हक, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद। मैच का समय : शाम 7.30 से

फाइनल में शेल्टन, आज ज्वेरेव से खिताबी मिड़त

यूएस ओपन : सेमीफाइनल में टियाफो को हराया

एजेसी ►► न्यूयॉर्क

अमेरिका के बेन शेल्टन ने हमवतन फ्रांसिस टियाफो को हराकर अमेरिकी ओपन के पुरुष एकल फाइनल में प्रवेश कर लिया, जहां उनका सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। स्थानीय खिलाड़ियों के बीच हुए इस मुकाबले को देखने के लिए स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था। दोनों का हौसला बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक और कई मशहूर हस्तियां मौजूद थीं। दोनों पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे थे। रविवार को होने वाले फाइनल में दर्शकों का समर्थन लगभग पूरी तरह शेल्टन के पक्ष में रहने की उम्मीद है। अब वह लंबे समय से चले आ रहे अमेरिकी ग्रैंड स्लैम खिताब के सुखे को खत्म करने की सबसे बड़ी उम्मीद बन गए हैं।



अपना सब कुछ झोंकने जा रहा हूं : शेल्टन

शेल्टन ने कहा, 'मैं यहां अपना सब कुछ झोंकने जा रहा हूं और कोर्ट पर कुछ भी बाकी नहीं छोड़ूंगा। उम्मीद है कि आप सभी आकर मेरा समर्थन करेंगे। आइए, इसे अमेरिका के लिए करते हैं।'

ज्वेरेव ने खाचानोव को हराया



ज्वेरेव ने पहले सेमीफाइनल में कारेन खाचानोव को 6-3, 7-6 (7), 7-6 (6) से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। टियाफो को तीसरी बार अमेरिकी ओपन के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले 2024 में उन्हें हमवतन टेलर फ्रिट्ज ने हराया था। टियाफो ने कहा, 'मैं ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचना चाहता था। जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा मुकाबला था। उसकी सर्विस भी बेहद अच्छी रही, जिसने मेरे लिए मुकाबला काफी मुश्किल बना दिया।' ज्वेरेव को लंबे समय तक ऐसे पुरुष खिलाड़ी के तौर पर देखा जाता रहा, जिन्होंने ग्रैंड स्लैम खिताब नहीं जीता था, लेकिन उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिना जाता था। इस साल फ्रेंच ओपन में आखिरकार उन्होंने यह इंतजार खत्म किया।

अमेरिकी सपने को साकार नहीं होने दूंगा : ज्वेरेव

ज्वेरेव ने कहा, 'उम्मीद है कि रविवार को मैं अमेरिकी सपने को साकार नहीं होने दूंगा।'

खबर संक्षेप

8 अक्टूबर से एपीएल हिस्सा लेंगी दीपिका

नई दिल्ली। चार बार की ओलंपियन दीपिका कुमारी और विश्व चैंपियनशिप रजत पदक विजेता अतनु दास 8 अक्टूबर से हैदराबाद में शुरू हो रही तीरंदाजी प्रीमियर लीग (एपीएल) के दूसरे सत्र में मेजबान रिकर्व टीम का हिस्सा होंगे। गत एशियाई चैंपियन धीरज बोम्पदेवरा समेत भारत के 36 सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज इसमें दस देशों के 12 अंतरराष्ट्रीय सितारों के साथ मुकाबला करेंगे। कंपाउंड वर्ग में कई बार विश्व का जीत चुकी एशियाई खेल चैंपियन ज्योति सुरेखा वेन्नम और अभिषेक वर्मा के साथ पूर्व विश्व चैंपियन ओजस प्रवीण देवताले उतरेंगे। विदेशी खिलाड़ियों में तोक्यो ओलंपिक 2020 चैंपियन तुर्किये के मेटे गाजोज, पेरिस ओलंपिक 2024 कांस्य पदक विजेता अमेरिका की कासे काउफोल्ड, ब्राजील के अलमेइडा और दुनिया की दूसरे नंबर की तीरंदाज ब्रिटेन की एला गिब्सन शामिल हैं।

20 से 23 नवंबर तक एशियाई कैडेट कप चेन्नई। उपमहाद्वीप के युवा तलवारबाजों के लिए एशियाई कैडेट कप 20 से 23 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट में 30 से अधिक देशों के 500 से अधिक खिलाड़ी, कोच, अधिकारी और तकनीकी अधिकारी भाग लेंगे। टूर्नामेंट तीन वर्गों एपी, फॉइल और साबर में आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन भारतीय तलवारबाजी संघ ने एशियाई तलवारबाजी परिषद के साथ मिलकर युवा कार्य और खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण और तमिलनाडु खेल विकास प्राधिकरण के साथ किया है। एफएआई महासचिव राजीव मेहता ने कहा, 'इससे एशिया के युवा तलवारबाजों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव मिलेगा और भविष्य में एशियाई खेलों, विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक में सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा।'

सूचना

सभी पाठकों से अनुरोध है कि हरिभूमि समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापनों (डिस्पले/क्लासीफाईड) में दिए गए तथ्यों/दावों के बारे में अपने विवेक से निर्णय लें और विज्ञापन के दावों की विश्वसनीयता को पछे। हरिभूमि समूह के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की विज्ञापनों के तथ्यों से सम्बन्धित कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

जूनियर एशिया कप हॉकी : फाइनल में टीम इंडिया, सुप्रिया ने लगाई हैट्रिक

एजेसी ►► मोकी

ड्रैग फ्लिकर सुप्रिया के तीन गोल की मदद से गत चैंपियन भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर एएचएफ जूनियर महिला एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया। सुप्रिया ने तीनों गोल पेनल्टी कॉर्नर पर किए। भारत का सामना अब चीन और जापान के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा।

दोनों टीमों ने संभलकर शुरूआत की लेकिन भारत ने 13वें मिनट में खाता खोला जब मधु सिद्ध ने शानदार फील्ड गोल पर टीम को 1-0 से बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में भारतीय खिलाड़ियों ने कोरियाई गोल पर लगातार हमले बोले। भारत को 17वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर पर सुप्रिया ने गोल करके बढ़त दुगुनी कर दी।



इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज की 3-0 से 'क्लीन स्वीप'

एजेसी ►► बर्मिंघम

इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ एजबेस्टन में खेले गए टेस्ट सीरीज के तीसरे और अंतिम मुकाबले को 8 विकेट से जीतकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया है। पाकिस्तान से मिले 130 रन के आसान टारगेट को मेजबान टीम ने मुकाबले के चौथे दिन 24.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम पहली पारी में 133 रन पर सिमट गई। आलम ये रहा कि इस पारी में 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके। सऊद शाकील ने सर्वाधिक 43 रन बनाए, जबकि मोहम्मद अब्बास ने 21 रन का पारी खेली। इनके अलावा, रजाउल्लाह ने टीम के खाते में 11 रन का योगदान दिया। मेजबान खेमे से जोश टंग ने 42 रन देकर 4 विकेट झटके, जबकि ओली रॉबिन्सन और जोफ्रा आर्चर ने 3-3 विकेट चटकाए।



पाक ने गलतियों से लिया सबक

पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में पिछली गलतियों से सबक लेते हुए 449 रन बनाए, मगर ये स्कोर मैच बचाने के लिए नाकामी था। मेहमान टीम ने शुरूआती 4 गेंदों में 2 विकेट खो दिए थे। उस समय तक खाता भी नहीं खुल सका था, लेकिन इसके बाद शान मसूद (95) ने अजान ओवैस (59) के साथ तीसरे विकेट के लिए 125 रन और कप्तान बाबर आजम (76) के साथ चौथे विकेट के लिए 89 रन जोड़े।

भारत ने गेंद पर बनाया दबदबा

भारत ने गेंद पर नियंत्रण के मामले में दबदबा बनाए रखा और 21वें मिनट में कोरियाई गोल के 23 मीटर के भीतर हवा में आई गेंद को भारतीय विंगर ने लपका और सर्कल के भीतर शानदार क्रॉस दिया। इसे सुखवीर ने गोल में बदलकर स्कोर 3-0 कर दिया। भारत को 33वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर की सुप्रिया ने गोल में बदला। दक्षिण कोरिया के लिए युरी जियोंग ने 41वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके स्कोर 4-1 किया। भारत ने आखिरी क्वार्टर में बेहतरीन डिफेंस का प्रदर्शन करते हुए कोरियाई हमलों को नाकाम कर दिया। भारत के लिए पांचवां गोल 56वें मिनट में सुप्रिया ने पेनल्टी कॉर्नर पर किया।

महिला एशिया कप : भारत की नजरें आठवें खिताब पर

एजेसी ►► दुबई

सात बार की चैंपियन भारतीय टीम की नजरें श्रीलंका के खिलाफ रविवार को महिला टी20 एशिया कप फाइनल में श्रीलंका को हराकर आठवीं बार खिताब जीतने पर लगी होंगी और इसके लिए शेफाली वर्मा के साथ दीपति शर्मा पर काफी दायरेमदार रहेगा। दो अर्धशतक समेत 168 रन बना चुकी शेफाली भारत की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज साबित हुई हैं और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं। धोमी और स्पिनरों की मददगार दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर भी उन्होंने सहज बल्लेबाजी की है। स्मृति मंथाना (154) ने एक शानदार शतक लगाया



लेकिन दो मैचों में दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सकी। शेफाली के प्रदर्शन में निरंतरता रही है। शेफाली को अपने चिर परिचित स्टोक्स खेलने में भी परेशानी नहीं आई जबकि दूसरे बल्लेबाज जूझते नजर आए हैं।

मैच का समय : रात 8 बजे

अमेरिकी ओपन जूनियर: सेमीफाइनल में हारी रेवती-एंटोनिना की जोड़ी

अमेरिकी जुड़वां बहनें अनिका और क्रिस्टीना पेनिकोवा जीतीं

एजेसी ►► न्यूयॉर्क

भारत की माया राजेश्वरन रेवती और उनकी यूक्रेनी जोड़ीदार एंटोनिना सुफोवा का शानदार सफर अमेरिकी ओपन जूनियर बालिका युगल के सेमीफाइनल में मिली हार के साथ समाप्त हो गया।



माया और एंटोनिना की गैर वरीयता प्राप्त जोड़ी को अमेरिकी जुड़वां बहनों अनिका और क्रिस्टीना पेनिकोवा से 6-7(2),

2-6 से हार का सामना करना पड़ा। भारत और यूक्रेन की इस जोड़ी ने हालांकि टूर्नामेंट में प्रभावशाली

दीपति ने दिखाया जौहर, आज श्रीलंका से मिड़त

श्रीलंका की कप्तान चामारी अटापट्टु के साथ सर्वाधिक 11 विकेट ले चुकी दीपति ने गेंदबाजी के अलावा बल्ले के जौहर भी दिखाए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में 6 गेंद में 13 रन बनाकर उन्होंने भारत को 150 रन के पास पहुंचाया। दीपति के साथ श्रीचरणी और प्रेमा रावत ने भी उम्दा स्पिन गेंदबाजी की है और इन तीनों ने टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाए रखा है। दोनों टीमों फाइनल तक के सफर में अपराजेय रही हैं और पिछली बार 2024 में भारत को श्रीलंका ने ही फाइनल में आठ विकेट से हराया था। अटापट्टु की टीम ने भी पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है और पाकिस्तान के खिलाफ जुझारूपन दिखाते हुए सेमीफाइनल में जीत दर्ज की। दो साल पहले दाम्बुला में हर्षिता और अटापट्टु ने मिलकर भारत को फाइनल में जीत दर्ज करने से रोका था।

मार्केट न्यूज

फिल्म 'हैवान' के रोमांचक सफर के साथ डा. आर्थो दे रहा मजबूत कदमों का भरोसा

फिल्म हैवान व आर्गुवैदिक 'डा. आर्थो' की विशेष बांड साझेदारी

चंडीगढ़। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म 'हैवान' एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जो अपराध, रोमांच और रहस्य से भरपूर कहानी को बड़े पर्दे पर प्रस्तुत करती है। फिल्म में अश्वय कुमार, सैफ अली खान, बोमन ईरानी, श्रिया पिलागांवकर और सैयामी खेर के साथ कई प्रतिभाशाली कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म के प्रमोशन के दौरान कलाकारों ने कहा कि चाहे जिंदगी में कितनी भी भागदौड़ और चुनौतियां क्यों न हों, मजबूत कदमों के साथ हर सफर आसान बनाया जा सकता है। ऐसे मजबूत कदमों के लिए चार्लिए डा. आर्थो एक्स्प्रेसर स्लीपर एवं शूज, जो हर पल देते हैं नई ऊर्जा, मजबूती और दर्द से पूरी आजादी। वहीं, फिल्म की सफलता की कामना करते हुए एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर डा. संजीव जुनेजा ने कहा कि रोमांच, रहस्य और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी कहानियों को प्रभावशाली तरीके से पर्दे पर प्रस्तुत करने वाली फिल्में दर्शकों को बांधे रखने के साथ उन्हें सोचने का अवसर भी देती हैं। उन्होंने फिल्म की पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए इसकी शानदार सफलता की कामना की। इस अवसर पर कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा कि डा. आर्थो एक्स्प्रेसर स्लीपर एवं शूज को पैरों की बेहतर देखभाल और आराम का ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। यह प्रोडक्ट डेली लाइफ में पैरों को आराम प्रदान करने के साथ-साथ एक्टिव और एनर्जेटिक लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने में सहायक है।



एशियन गेम्स : कुश्ती में म्हारी बेटियों का दबदबा

प्रदेश की 6 धुरंधर बेटियां जापान में दिखाएंगी दमखम

हरिभूमि न्यूज ►►रोहतक

एशियन गेम्स के लिए 6 सदस्यीय भारतीय महिला कुश्ती टीम का आधिकारिक हो चुका है। खास बात यह है कि इस पूरी टीम में हरियाणा की बेटियों ने अपना दबदबा बनाते हुए सभी भार वर्ग में अपनी जगह पक्की की है। इसमें दीपांशी (50 किग्रा), अंतिम पंचाल (53 किग्रा), मनीषा भनवाला (57 किग्रा), मानसी अहलावत (62 किग्रा), निशा दहिया (68 किग्रा) और प्रिया मलिक (76 किग्रा)। सभी महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले भी देश



का नाम रोशन किया है। एशियन गेम्स 19 सितंबर से चार अक्टूबर तक जापान में आयोजित किए जाएंगे। इसमें तीन खिलाड़ी रोहतक के छोटाराम स्टेडियम में

कोच मनदीप के पास अभ्यास करती है। दीपांशी, मनीषा और मानसी अहलावत शामिल हैं। हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रमेश ने खुशी जाहिर करते हुए

कहा कि राज्य के लिए यह गर्व का क्षण है। वहीं, कोच मनदीप ने खिलाड़ियों की तैयारियों पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि इन सभी ने ट्रेनिंग कैंप में अपनी

फिटनेस और तकनीक पर बहुत काम किया है। उन्होंने सभी महिला पहलवानों को एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।



**सच्ची
सहेली®**

हरिभूमि कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मदद एवं प्रकाशक देवेन्द्र सिंह बाल्यान् द्वारा हरिभूमि पब्लिकेशंस, चलिआना मोड, दिल्ली रोड, रोहतक-124517 से मद्रित एवं हरिभूमि कार्यालय, 129, सांस्पर्ट सेंटर, पंजाबी बाग, पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली-110035 से प्रकाशित। सम्पादक : डॉ. हिमांशु द्विवेदी। आरम्भ आर्द नं 69631/1998, फोन : 011-40451115/16, 40451109